

जन जन की बात जन जन तक

साप्ताहिक

जन जन विचार



বাইজৰ কথা বাইজৰ মাজলৈ

সাপ্তাহিক

জন জন বিচাৰ

WEEKLY TRILINGUAL NEWSPAPER

Language : Hindi, Assamese & English

WEBSITE : www.janjanvichar.in

VOICE OF ALL, FOR ALL

WEEKLY

JAN JAN VICHAR

RNI Regd No. ASMUL/25/A2367::Guwahati, Friday, 23 October 2026 :: Year-1 Vol-41 Issue-20 :: शुक्रवार। 23 अक्टूबर 2026। शक संवत 1948। आश्विन। शुक्ल। द्वादशी। :: पृष्ठ-20। मूल्य-15 रुपए

जन चिंतन

धनेश्वर चौधरी

सड़क से पहुंचेंगे संसद!

सत्ता चाहिए, लेकिन जनता का जनादेश कब मिलेगा-शायद विपक्ष की बेचैनी का सबसे बड़ा सवाल यही है। संजय राउत के 'रेजीम चेंज' के दावे और राहुल गांधी की वापसी के बाद सत्ता परिवर्तन की उम्मीदों ने सियासी पारा चढ़ा दिया है। मगर सवाल सीधा है-क्या विपक्ष चुनावी मैदान में सरकार को हराने की तैयारी कर रहा है या सड़क के शोर को सत्ता परिवर्तन का विकल्प मान बैठा है?

लोकतंत्र में सड़क की अपनी ताकत है। वहीं से अन्याय के खिलाफ आवाज उठती है, सरकारों को जवाबदेह बनाया जाता है और जनआंदोलन जन्म लेते हैं। लेकिन सड़क पर जुटी भीड़ को जनादेश समझ लेना राजनीतिक आत्ममुग्धता है। नारे सरकार को घेर सकते हैं, प्रदर्शन व्यवस्था पर दबाव बना सकते हैं, लेकिन सत्ता का फैसला मतदाता करता है-नेताओं शेष पृष्ठ 2 पर

भारत में 'रेजीम चेंज' की हुंकार



'रिजीम चेंज' की बात करने में कुछ गलत नहीं : नेहा बोरा

(पृष्ठ 2 पर)

जन जन विचार

...✍नई दिल्ली

भारत में सत्ता परिवर्तन की बहस अब एक नए और तीखे मोड़ पर पहुंच गई है। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) और मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच 'रेजीम चेंज' यानी सत्ता-व्यवस्था बदलने की खुली घोषणाओं ने राजनीतिक टकराव बढ़ा दिया है। वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने साफ कहा कि वे सत्ता परिवर्तन चाहते हैं, जबकि छात्र नेता नेहा बोरा ने बांग्लादेश के युवा आंदोलन का उल्लेख करते हुए कहा कि उसने भारत के युवाओं को रास्ता दिखाया है। भाजपा ने इन बयानों को निर्वाचित सरकार को सड़क के दबाव से हटाने की कोशिश से जोड़ा है।

विरोध प्रदर्शनों की शुरुआत मतदाता सूची के पुनरीक्षण, कथित अनियमितताओं और निर्वाचन आयुक्त के इस्तीफे की मांग से हुई थी। विपक्षी दलों और शेष पृष्ठ 3 पर

राहुल के वियतनाम से लौटते ही होगा सत्ता परिवर्तन : संजय राउत



नई दिल्ली। *शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत ने भारत में सत्ता परिवर्तन ('रेजीम चेंज') को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा, 'हो जाएगा रेजीम चेंज, आप देखते रहिए। राहुल गांधी वियतनाम गए हैं न, आने के बाद देखो।' उनका यह बयान निर्वाचन आयोग के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों और सत्ता परिवर्तन को लेकर जारी राजनीतिक विवाद के बीच आया है। इससे पहले राउत ने अगले छह महीने में महाराष्ट्र और देश में सत्ता परिवर्तन होने का दावा भी किया था*

फ्रांस की सड़कों पर आग, धधका यूरोप

नई दिल्ली। यूरोप की चमकदार सड़कों पर इन दिनों असंतोष की लपटें दिखाई दे रही हैं। फ्रांस में महंगाई, शिक्षा व्यवस्था की बदहाली, बढ़ती जीवन-यापन लागत और सार्वजनिक सेवाओं को लेकर शुरू हुआ विरोध हिंसक झड़पों, आगजनी और लूटपाट तक पहुंच गया। दूसरी ओर स्पेन और पुर्तगाल में महंगे मकानों और किराये के खिलाफ प्रदर्शन तेज हुए हैं, जबकि इटली और अल्बानिया में भी आर्थिक परेशानियों तथा सरकारी व्यवस्था के प्रति नाराजगी सड़कों पर दिखाई दे रही है। सवाल अब केवल कानून-व्यवस्था का नहीं है, बल्कि यह भी है कि यूरोप की स्थापित लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं आम नागरिकों की बढ़ती बेचैनी का समाधान क्यों नहीं कर पा रही हैं।

फ्रांस में 17 अक्टूबर को हुए व्यापक प्रदर्शनों ने सरकार के सामने गंभीर चुनौती खड़ी कर दी। देशभर में लगभग शेष पृष्ठ 7 पर

विदेशी संगठनों के साथ मिलकर देश को अस्थिर करने की साजिश रच रहे राहुल गांधी : भाजपा

जन जन विचार

...✍नई दिल्ली

भारत में विरोध प्रदर्शनों को लेकर सियासी संग्राम तेज हो गया है। भाजपा ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर विदेशी संगठनों के साथ कथित संबंधों के जरिए देश में अराजकता फैलाने और संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने की कोशिश का आरोप लगाया है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर फ्रांस, स्पेन और अल्बानिया में हुए प्रदर्शनों का हवाला देते हुए

फ्रांस से दिल्ली तक नेटवर्क का आरोप

दावा किया कि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की गतिविधियों और भारत में जारी राजनीतिक आंदोलनों के बीच संबंधों की पड़ताल जरूरी है।

भाटिया ने प्रोग्रेसिव इंटरनेशनल और फ्रांस स्थित इंडियन अलायंस पेरिस का नाम लेते हुए कांग्रेस से सवाल किया कि राहुल गांधी और इन संगठनों के बीच क्या संबंध हैं, बैठकों में किन मुद्दों पर चर्चा हुई और क्या किसी तरह का समझौता किया गया। उन्होंने विदेशी फंडिंग के स्रोतों और कथित अंतर्राष्ट्रीय संपर्कों पर भी जवाब मांगा।

भाजपा प्रवक्ता ने फॉक्स न्यूज डिजिटल की शेष पृष्ठ 3 पर



एआई की मदद से हो रही साइबर ठगी

जन जन विचार
...✍ नई दिल्ली

पीएनबी ने ग्राहकों को किया सतर्क

- फर्जी आवाज, डीपफेक वीडियो और केवाईसी अपडेट के नाम पर ठगी से बचने की सलाह
- धोखाधड़ी होने पर 1930 पर करें शिकायत

डिजिटल बैंकिंग के बढ़ते इस्तेमाल के बीच साइबर अपराधी अब कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और नई तकनीकों का सहारा लेकर लोगों को ठगी का शिकार बना रहे हैं। पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) ने ग्राहकों को आगाह करते हुए कहा है कि साइबर ठग परिचितों की आवाज और चेहरे की नकल करने से लेकर बैंक के नाम पर फर्जी संदेश भेजने तक के तरीके अपना रहे हैं। बैंक ने ग्राहकों से किसी भी संदिग्ध संदेश, फोन कॉल या धन हस्तांतरण के अनुरोध पर बिना सत्यापन भरोसा नहीं करने की अपील की है।

राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा जागरूकता माह के अवसर पर पीएनबी के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी अशोक चंद्र ने ग्राहकों के नाम जारी संदेश में कहा कि साइबर ठगी के कई मामलों में लोगों के विश्वास, डर और जल्दबाजी का फायदा उठाया जाता है। उन्होंने बैंकिंग संबंधी गोपनीय जानकारी सुरक्षित रखने और किसी भी लेनदेन से पहले सतर्क रहने पर जोर दिया।

परिचित की आवाज में भी हो सकती है ठगी

बैंक के अनुसार, साइबर अपराधी कृत्रिम बुद्धिमत्ता के जरिए परिवार के सदस्यों, मित्रों या परिचितों की आवाज और वीडियो की नकल कर सकते हैं। वे किसी आपात स्थिति का हवाला देकर तत्काल पैसे भेजने का दबाव बनाते हैं। इसी तरह, फर्जी ई-मेल, एसएमएस और संदेशों के जरिए केवाईसी अपडेट, खाते को बंद करने की चेतावनी, पुरस्कार, धनवापसी और डिजिटल गिरफ्तारी जैसे बहानों से लोगों को ठगा जाता है। पीएनबी ने सलाह दी है कि यदि कोई परिचित बनकर तत्काल धनराशि मांगता है, तो पहले फोन काटकर उसके पहले से सुरक्षित नंबर पर संपर्क करें। किसी अनजान लिंक पर क्लिक न करें और अज्ञात स्रोत से मोबाइल अनुप्रयोग या एपीके फाइल डाउनलोड करने से बचें।

ओटीपी और यूपीआई पिन किसी से न करें साझा

बैंक ने स्पष्ट किया है कि वह ग्राहकों से कभी भी ओटीपी, यूपीआई पिन, इंटरनेट या मोबाइल बैंकिंग का पासवर्ड और कार्ड का सीवीवी नंबर नहीं मांगता। ग्राहकों को मजबूत एवं अलग-अलग पासवर्ड रखने, मोबाइल और कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर को नियमित रूप से अद्यतन करने तथा जहां सुविधा उपलब्ध हो, वहां दो-स्तरीय सुरक्षा अपनाने की सलाह दी गई है।

ठगी होने पर तुरंत करें शिकायत

पीएनबी ने ग्राहकों से कहा है कि खाते में अनधिकृत लेनदेन दिखने या साइबर ठगी का संदेह होने पर संबंधित बैंकिंग सुविधा या कार्ड को सुरक्षित करने के लिए तत्काल कदम उठाएं। इसके साथ ही राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन 1930 पर सूचना दें और https://cybercrime.gov.in/ पर शिकायत दर्ज कराएं। बैंक ने अपनी 24 घंटे उपलब्ध ग्राहक सेवा के नंबर 1800 1800 और 1800 2021 भी साझा किए हैं। ग्राहक care@pnb.bank.in पर ई-मेल के जरिए भी संपर्क कर सकते हैं।

अशोक चंद्र ने कहा कि साइबर सुरक्षा साझा जिम्मेदारी है। बैंक की सुरक्षा व्यवस्था के साथ ग्राहकों की जागरूकता और सतर्कता ही ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचाव का सबसे प्रभावी माध्यम है। उन्होंने ग्राहकों से किसी भी लिंक पर क्लिक करने, जानकारी साझा करने या लेनदेन करने से पहले रुकने, सत्यापन करने और सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की।

बंगाईगांव के होटल में मिला असम के डीएसपी का शव, बीमारी की आशंका

बंगाईगांव। असम के मुख्यमंत्री सतर्कता प्रकोष्ठ में तैनात पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) खर्गेश्वर राभा का शव 22 अक्टूबर को बंगाईगांव के एक होटल के कमरे से बरामद हुआ। शव आंशिक रूप से सड़ चुका था। जिला वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) नुमल महतो ने अधिकारी के स्वास्थ्य संबंधी समस्या से ग्रस्त होने की आशंका जताई है। हालांकि, मौत के वास्तविक कारणों की पुष्टि जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही होगी।

पुलिस के अनुसार, राभा 18 अक्टूबर को दुर्गा पूजा की छुट्टियों के दौरान होटल जाह्नवी रीजेंसी के कमरा नंबर 102 में ठहरे थे। शव मिलने की सूचना के बाद उनकी पत्नी और परिवार के अन्य सदस्य होटल पहुंचे। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए बंगाईगांव मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया।

'रिजीम चेंज' की बात करने में कुछ गलत नहीं : नेहा बोरा

जन जन विचार
...✍ नई दिल्ली

दिल्ली हाईकोर्ट में ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (एआईएसए) की अध्यक्ष नेहा बोरा की ओर से पेश वकील ने दलील दी कि लोकतंत्र में 'रिजीम चेंज' यानी सत्ता परिवर्तन की बात करने में कुछ भी गलत नहीं है। यह दलील उस याचिका की सुनवाई के दौरान दी गई, जिसमें नेहा बोरा ने स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट (एसईएम) के उस नोटिस को चुनौती दी है, जिसके तहत उन्हें 10,000 रुपए का बॉन्ड भरने और शांति बनाए रखने की शर्त पूरी करने को कहा गया था।

सुनवाई के दौरान नेहा बोरा की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन ने कहा कि लोकतंत्र में सत्ता परिवर्तन की मांग करना कोई गलत बात नहीं है। अदालत में इस मामले को लेकर यह सवाल भी उठा कि क्या केवल ऐसी राजनीतिक मांग के आधार पर किसी व्यक्ति से बॉन्ड भरवाने और शांति बनाए रखने की शर्त पूरी करने की अपेक्षा की जा सकती है।

रपोर्ट के मुताबिक, सुनवाई के दौरान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) चेतन शर्मा ने अदालत के सामने प्रशासन की ओर से रखी गई दलीलों का उल्लेख किया। उनका कहना था कि संबंधित अधिकारियों को आशंका थी कि यदि समय रहते कदम नहीं उठाए जाते, तो राजधानी में कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती थी। एएसजी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धाराओं 126 और 130 का हवाला देते हुए कहा कि परिस्थितियों के अनुसार इन प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जा सकती है। सुनवाई के दौरान प्रशासन की ओर से यह तर्क भी सामने आया कि सत्ता परिवर्तन लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत मतदान के माध्यम से होना चाहिए, न कि ऐसे जमावड़ों के जरिए जिनसे सार्वजनिक व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका हो।

पृष्ठ 1 का शेषांश...

सड़क से पहुंचेंगे संसद!

की भविष्यवाणियां नहीं।

विपक्ष को आखिर जनता को क्या जवाब देना है? महंगाई पर उसका विकल्प क्या है? बेरोजगारी से निपटने की उसकी योजना क्या है? किसानों, युवाओं और मध्यम वर्ग के लिए उसके पास कौन-सा ठोस कार्यक्रम है? इन सवालों पर चुप्पी और सत्ता परिवर्तन के बड़े-बड़े दावे-क्या इसी से राजनीतिक विश्वसनीयता बनेगी?

लेकिन सत्तापक्ष भी भ्रम में न रहे। चुनाव जीतना जनता की हर शिकायत का खंडन नहीं है। बहुमत जवाबदेही से छूट का प्रमाणपत्र नहीं और विपक्ष की आलोचना को साजिश बताकर खारिज करना लोकतांत्रिक मर्यादा नहीं है।

सत्ता सड़क के दबाव से डगमगा सकती है, लेकिन लोकतंत्र में उसका वैध हस्तांतरण जनादेश से ही होता है। विपक्ष को यदि वास्तव में बदलाव चाहिए, तो उसे नारों की आंधी नहीं, विश्वास की जमीन तैयार करनी होगी। क्योंकि राजनीति में सत्ता परिवर्तन की घोषणा करना आसान है, जनता को परिवर्तन के लिए तैयार करना कठिन।

आखिर सवाल यही है-विपक्ष देश बदलने निकला है या सिर्फ सरकार बदलने का सपना बेच रहा है?

राशिफल

23 से 29 अक्टूबर, 2026 ॥ विक्रम संवत 2083-**मास** : आश्विन, **पक्ष** : शुक्ल, **तिथि** :द्वादशी

मेष : नौकरी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। खर्चों पर नियंत्रण रखें। परिवार में तालमेल बनाए रखें और गुस्से से बचें।

वृषभ : कारोबार में लाभ के अवसर मिल सकते हैं। आर्थिक मामलों में सावधानी बरतें। परिवार का सहयोग मिलेगा।

मिथुन : कार्यक्षेत्र में नए अवसर मिल सकते हैं। पैसों के लेन-देन में सतर्क रहें। रिश्तों में गलतफहमी दूर करने का प्रयास करें।

कर्क : काम का दबाव बढ़ सकता है। घरेलू खर्चों पर ध्यान दें। परिवार के साथ समय बिताने से मन प्रसन्न रहेगा।

सिंह : कार्यक्षेत्र में आपकी जिम्मेदारी बढ़ सकती है। निवेश में जल्दबाजी न करें। जीवनसाथी के साथ तालमेल बनाए रखें।

कन्या : अधूरे काम पूरे हो सकते हैं। आर्थिक मामलों में सुधार की उम्मीद है। सेहत का ध्यान रखें और आराम के लिए समय निकालें।

तुला : नौकरी और कारोबार में नए अवसर मिल सकते हैं। खर्चों पर नियंत्रण रखें। परिवार में बातचीत से समस्याएं सुलझ सकती हैं।

वृश्चिक : कामकाज में प्रगति के अवसर मिल सकते हैं। आर्थिक फैसले सोच-समझकर लें। रिश्तों में भरोसा बनाए रखें।

धनु : नई योजनाओं में सफलता के अवसर मिल सकते हैं। अनावश्यक खर्च से बचें। परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा।

मकर : काम में व्यस्तता बढ़ सकती है। बचत पर ध्यान दें। परिवार का सहयोग मिलेगा और पुरानी समस्याएं सुलझ सकती हैं।

कुंभ : कार्यक्षेत्र में नए संपर्क लाभदायक हो सकते हैं। पैसों के मामले में सावधानी बरतें। विवादों से दूर रहें।

मीन : रचनात्मक कामों में रुचि बढ़ेगी। आर्थिक मामलों में सोच-समझकर निर्णय लें। परिवार में सुखद माहौल बना रह सकता है।

सप्ताह के पर्व/त्योहार

23 अक्टूबर (शुक्रवार) : प्रदोष व्रत
25 अक्टूबर (रविवार) : शरत पूर्णिमा, कोजागरी
26 अक्टूबर (सोमवार) : महर्षि बाल्मिकी जयंती
27 अक्टूबर (मगलवार) : कार्तिक मास आरंभ, अशून्यशयन व्रत
29 अक्टूबर (गुरुवार) : संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी व्रत

●ज्योतिर्विद् आचार्य अखिलेश्वर शुक्ल
भाग्योदय : पहला तल्ला, सेंट्रल प्लाजा, एमएस रोड
फैंसी बाजार, गुवाहाटी-781001 मो.-94350 40387

धन दिशा



बच्चों की पढ़ाई का खर्च

दुर्गा पूजा का समय है। घर में मेहमान हैं, बच्चे खुश हैं, और माहौल उत्सव का है। लेकिन इसी उत्सव में जब परिवार एक साथ बैठता है तो अक्सर एक बात निकलती है, 'बेटे को इंजीनियरिंग करानी है' या 'बेटी डॉक्टर बनेगी।' सपने बड़े हैं, और होने भी चाहिए। लेकिन सवाल यह है – क्या हम उन सपनों के लिए तैयार हैं?

आज की पढ़ाई कितनी महंगी है? आज एक सामान्य इंजीनियरिंग कोर्स में 10-15 लाख रुपए लगते हैं। मेडिकल में 50 लाख से ऊपर। MBA या विदेश में पढ़ाई का सपना हो तो 30-80 लाख तक जा सकता है। और शिक्षा की महंगाई यानी education inflation हर साल लगभग 10-12% बढ़ रही है। मतलब, आज जो खर्च 10 लाख है, वह 10 साल बाद 25-30 लाख हो सकता है।

SIP से शुरुआत करें-जितनी जल्दी, उतना बेहतर। अगर बच्चा अभी 5 साल का है और 13 साल बाद इंजीनियरिंग करनी है, तो आज से 3,000 रुपए प्रति माह का SIP शुरू करें। 12% औसत रिटर्न पर 13 साल में लगभग 12 लाख रुपए जमा होंगे- बिना एक भी रुपए की उधारी के। यही काम अगर 5 साल बाद शुरू किया तो उतनी ही रकम जुटाने के लिए 7,000-8,000 रुपए प्रति माह चाहिए।

कौन से फंड चुनें? बच्चों की पढ़ाई के लिए समय सीमा अगर 10 साल से ज़्यादा है तो Flexi Cap या Large & Mid Cap म्यूचुअल फंड अच्छे विकल्प हैं। 5-10 साल के लिए Balanced Advantage Fund सुरक्षित रहता है। 3-5 साल में पैसा चाहिए तो Debt Fund में रखें।

Sukanya Samriddhi Yojana-बेटी है तो जरूर देखें। अगर घर में 10 साल से कम उम्र की बेटी है तो Sukanya Samriddhi Yojana में निवेश करें। सरकारी गारंटी, टैक्स लाभ, और अभी 8.2% ब्याज- यह स्कीम बेटी की पढ़ाई और शादी दोनों के लिए काम आती है।

एक जरूरी सलाह। एजुकेशन लोन उपाय है, योजना नहीं। बच्चे पर पढ़ाई का बोझ शुरू होने से पहले ही कर्ज का बोझ न डालें। आज पूजा की खुशी में परिवार के साथ बैठकर यह निर्णय करें कि हर महीने कितना अलग रखना है- और कल से SIP शुरू करें।

अगले हफ्ते : धनतेरस - सोना खरीदें या नहीं? क्या खरीदें, क्या न खरीदें, और कैसे खरीदें समझदारी से।

इस कॉलम के लिए आपका कोई सवाल है? हमें भेजिए

-कोमल जैन

पर्सनल फाइनेंस एक्सपर्ट, संस्थापक, वेल्थप्लायर्स- मो. 9004510577

मेघालय में खेती की नई संभावनाएं 3.40 लाख हेक्टेयर भूमि चिह्नित

जन जन विचार
...✍ शिलांग

मेघालय में कृषि विकास की नई संभावनाओं का पता चला है। उपग्रह तस्वीरों और भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) तकनीक की मदद से राज्य में 3,40,673.36 हेक्टेयर ऐसी भूमि की पहचान की गई है, जहां लंबे समय से खेती नहीं हो रही है। यह क्षेत्र मेघालय के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 15.2 प्रतिशत है। वैज्ञानिक अध्ययन में सामने आए इन निष्कर्षों से राज्य में कृषि भूमि के बेहतर उपयोग, टिकाऊ खेती और संसाधनों के नियोजित प्रबंधन की संभावनाएं बढ़ी हैं। हालांकि, इस भूमि को खेती के लिए तैयार करने से पहले मिट्टी, ढलान, जल उपलब्धता और आर्थिक व्यवहार्यता की विस्तृत जांच जरूरी होगी।

'जर्नल ऑफ जियोग्राफी, एनवायरनमेंट एंड अर्थ साइंस इंटरनेशनल' में इस महीने प्रकाशित अध्ययन के अनुसार, आधुनिक अंतरिक्ष तकनीक के जरिए राज्य में लंबे समय से खेती से बाहर पड़ी भूमि का वर्गीकरण किया गया है। शोधकर्ताओं का मानना है कि यह आकलन कृषि विकास की योजना बनाने और उपलब्ध भूमि संसाधनों के प्रभावी इस्तेमाल की दिशा में महत्वपूर्ण आधार बन सकता है।

कम वनस्पति वाले क्षेत्र में सबसे अधिक संभावना

अध्ययन में चिह्नित भूमि का सबसे बड़ा हिस्सा कम घनी झाड़ियों वाली भूमि का है। इसका क्षेत्रफल 2,06,595.18 हेक्टेयर है, जो कुल चिह्नित भूमि का 60.64 प्रतिशत है। शोधकर्ताओं ने इस श्रेणी को दोबारा खेती के लिए उपयोगी बनाने की प्राथमिकता के आधार पर 100 में से 95 अंक दिए हैं।

घनी झाड़ियों वाली भूमि 99,488.89 हेक्टेयर में फैली है, जो चिह्नित क्षेत्र का 29.20 प्रतिशत है। इसे 80 अंक दिए गए हैं। वहीं, झूम खेती से जुड़े क्षेत्रों का रकबा 34,331.34 हेक्टेयर है, जो कुल क्षेत्र का 10.08 प्रतिशत है। इस श्रेणी को 60 अंक मिले हैं। घास के मैदान और चरागाह केवल 257.94 हेक्टेयर में फैले हैं, जिन्हें 25 अंक दिए गए हैं।

इन आंकड़ों से संकेत मिलता है कि कम घनी झाड़ियों वाले क्षेत्रों के उपयोग की संभावनाओं का पहले आकलन किया जा सकता है। हालांकि, प्राथमिकता के लिए दिए गए अंक अपने आप में किसी भूमि की खेती के लिए उपयुक्तता का अंतिम प्रमाण नहीं हैं।

उपग्रह से तैयार हुआ भूमि का नक्शा

यह अध्ययन नॉर्थ-ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, तुरा और उमियाम स्थित नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशंस सेंटर (एनईएसएसी) से जुड़े रैनक मीना, चंदन गोस्वामी, सीपी सुरेश और अकमौल हक ने किया। शोधकर्ताओं ने वर्ष 2025-26 में एलआईएसएस-4 सेंसर से प्राप्त बहुवर्णक्रमीय उपग्रह तस्वीरों का उपयोग किया। इनके आधार पर भूमि को चार श्रेणियों में बांटकर उसका क्षेत्रफल निर्धारित किया गया।

जीआईएस तकनीक के जरिए तैयार यह आकलन प्रशासन को उन क्षेत्रों की पहचान करने में मदद कर सकता है, जहां आगे विस्तृत सर्वेक्षण और कृषि विकास की योजनाएं बनाई जा सकती हैं। इससे भूमि उपयोग की प्राथमिकताएं तय करने और उपलब्ध संसाधनों के बेहतर प्रबंधन में भी सहायता मिल सकती है।

खेती शुरू करने से पहले कई चुनौतियों की जांच जरूरी

मेघालय जैसे पहाड़ी राज्य में किसी भूमि का खाली या कम वनस्पति वाला होना यह साबित नहीं करता कि वहां आसानी से खेती की जा सकती है। अध्ययन में मिट्टी की गुणवत्ता, भूमि की ढलान, सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता, सड़क संपर्क और खेती की लागत जैसे पहलुओं का विस्तृत आकलन नहीं किया गया है। इसलिए चिह्नित पूरी भूमि को तत्काल कृषि योग्य मानना उचित नहीं होगा। इसके अलावा, झूम खेती वाले क्षेत्रों के मामले में स्थानीय समुदायों की आजीविका और पारंपरिक कृषि पद्धतियों को ध्यान में रखना भी आवश्यक होगा। भूमि के उपयोग में बदलाव करते समय पर्यावरणीय संतुलन और स्थानीय जरूरतों के बीच तालमेल बनाना महत्वपूर्ण रहेगा। अब असली चुनौती इस पहचान को जमीन पर परिणाम में बदलने की है।

पृष्ठ 1 का शेषांश...

भारत में 'रेजीम चेंज' की ...

प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि मतदाता सूची से बड़ी संख्या में नाम हटाए जाने से पात्र मतदाताओं के अधिकार प्रभावित हो सकते हैं। निर्वाचन आयोग की ओर से पुनरीक्षण को मतदाता सूची दुरुस्त करने की प्रक्रिया बताया गया है। इन आरोपों और दावों पर विवाद जारी है।

लेकिन जब आंदोलन के प्रमुख चेहरों में शामिल लोग खुलकर 'रेजीम चेंज' की बात करने लगें और बांग्लादेश के सत्ता परिवर्तन का उदाहरण सामने रखें, तो बहस का दायरा बढ़ना स्वाभाविक है। अब सवाल उठ रहा है कि आंदोलन का लक्ष्य निर्वाचन प्रक्रिया में सुधार तक सीमित है या इसे व्यापक सत्ता परिवर्तन के अभियान में बदलने की कोशिश हो रही है।

भाजपा का आरोप है कि विपक्ष और उससे जुड़े कुछ संगठन बांग्लादेश जैसे घटनाक्रम से प्रेरणा लेकर भारत में अस्थिरता पैदा करना चाहते हैं। पार्टी का कहना है कि सरकार बदलने का रास्ता चुनाव है, न कि हिंसा या असंवैधानिक दबाव। हालांकि, किसी संगठित साजिश या विदेशी हस्तक्षेप के आरोप को स्थापित करने के लिए ठोस प्रमाण जरूरी हैं।

दूसरी ओर, कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि भारत न बांग्लादेश है और न फ्रांस। उनके अनुसार, विपक्ष की मांग स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने तथा मतदाता सूची से जुड़े सवालों का समाधान कराने की है। उन्होंने शांतिपूर्ण विरोध का समर्थन करते हुए हिंसा को अस्वीकार किया। कांग्रेस का तर्क है कि लोकतंत्र में सरकार बदलने की मांग करना अपने आप में असंवैधानिक नहीं है; सरकार बदलने का फैसला मतदाता चुनाव के जरिए करते हैं।

मालूम हो कि बांग्लादेश में 2024 का छात्र आंदोलन सरकारी नौकरी में आरक्षण के विरोध से शुरू हुआ था, लेकिन बाद में तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार के खिलाफ व्यापक आंदोलन में बदल गया और सरकार गिर गई। भारत में बांग्लादेश का संदर्भ इसी कारण राजनीतिक रूप से संवेदनशील हो गया है। लेकिन दोनों देशों की राजनीतिक परिस्थितियों, संस्थागत व्यवस्थाओं और घटनाक्रम को समान मान लेना अपने आप में पर्याप्त विश्लेषण नहीं होगा।

भारत में सरकार बदलने की इच्छा जताना और चुनाव के जरिए उसे बदलने के लिए अभियान चलाना लोकतांत्रिक राजनीति का हिस्सा है। लेकिन हिंसा, जबरदस्ती या संवैधानिक प्रक्रिया को दरकिनार करके सत्ता हासिल करने का प्रयास अलग सवाल खड़ा करता है। इसलिए 'रेजीम चेंज' शब्द के इस्तेमाल से ही किसी साजिश का निष्कर्ष निकालना उचित नहीं, लेकिन आंदोलन के नेताओं से यह पूछना भी स्वाभाविक है कि वे जिस परिवर्तन की बात कर रहे हैं, उसका रास्ता क्या है।

विदेशी संगठनों के साथ ...

एक रिपोर्ट का हवाला दिया, जिसमें नौ देशों में 101 संगठनों के प्रदर्शनों के आयोजन, समन्वय या प्रचार में शामिल होने का दावा किया गया है। भाटिया के अनुसार, कुछ अंतर्राष्ट्रीय समूह विभिन्न देशों में विरोध आंदोलनों को बढ़ावा देने और उनके संदेश को व्यापक स्तर पर प्रसारित करने में भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने अप्रैल 2025 में दिल्ली के 10 जनपथ पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी की एक प्रतिनिधिमंडल के साथ हुई मुलाकात का भी उल्लेख किया। भाजपा ने इस बैठक के उद्देश्य और उसमें हुई चर्चा पर कांग्रेस से स्पष्टीकरण मांगा। भाटिया ने कहा कि शांतिपूर्ण विरोध लोकतंत्र का अधिकार है, लेकिन हिंसा, आगजनी, तोड़फोड़ और संवैधानिक संस्थाओं को नुकसान पहुंचाना किसी भी सूरत में जायज नहीं ठहराया जा सकता। उन्होंने दिल्ली के प्रदर्शनों और विदेशों में हुई घटनाओं के बीच कथित समानताओं को लेकर भी सवाल उठाए।

संपादकीय

आजम-अखिलेश मुलाकात

रामपुर जेल में आजम खान से अखिलेश यादव की मुलाकात महज दो नेताओं की भेंट नहीं, बल्कि 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के राजनीतिक संदेश का हिस्सा भी है। अखिलेश का कहना-'आजम थे, आजम हैं और आजम रहेंगे'-पार्टी के पुराने सहयोगी के प्रति समर्थन जताता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या भावनात्मक बयानबाजी ही उस राजनीतिक चुनौती का जवाब है, जिसका सामना उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी कर रही है?

अखिलेश यादव ने आजम खान और उनके परिवार के साथ अन्याय होने का आरोप लगाया तथा उनके खिलाफ दर्ज मुकदमों को राजनीतिक प्रतिशोध से जोड़ा। इन आरोपों की सच्चाई का फैसला तथ्यों और न्यायिक प्रक्रिया के आधार पर होना चाहिए। किसी नेता का जेल में होना अपने आप में उसे दोषी या निर्दोष घोषित करने का आधार नहीं हो सकता। यही लोकतांत्रिक न्याय का मूल सिद्धांत है।

लेकिन राजनीति का एक दूसरा पक्ष भी है। आजम खान समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और रामपुर की राजनीति में प्रभावशाली चेहरा रहे हैं। ऐसे में अखिलेश की मुलाकात पार्टी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों को एकजुट करने का संदेश देती है। साथ ही, यह सवाल भी उठता है कि क्या सपा अपनी राजनीतिक रणनीति को कुछ प्रमुख चेहरों और भावनात्मक मुद्दों तक सीमित रखेगी, या जनता के रोजमर्रा के सवालों पर भी उतनी ही गंभीरता दिखाएगी?

उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून-व्यवस्था और किसानों की समस्याएं किसी एक मुलाकात से हल नहीं होंगी। भाजपा को चुनौती देने के लिए सपा को केवल आरोपों से आगे बढ़कर ठोस नीतियां और जवाबदेह नेतृत्व प्रस्तुत करना होगा।

हिंदी का विरोध नहीं भाषाओं का समन्वय जरूरी

भाषा संवाद का माध्यम है, राजनीतिक वर्चस्व का हथियार नहीं। कोलकाता नगर निगम के दुर्गापूजा पोस्टर में बांग्ला और हिंदी के मेल से तैयार वाक्य 'मायेर कोरबो स्वच्छता से स्वागत' पर विवाद और फिर पोस्टर वापस लेने का घटनाक्रम इसी सवाल को सामने लाता है। यदि दो भाषाओं का सहज संगम भी राजनीतिक चश्मे से देखा जाएगा, तो भाषायी सौहार्द कैसे मजबूत होगा? हिंदी का विरोध करने वालों को यह समझना चाहिए कि किसी भाषा का विस्तार दूसरी भाषा के विनाश की शर्त पर नहीं होना चाहिए। बांग्ला, तमिल, असमिया और दूसरी भारतीय भाषाएं हमारी सांस्कृतिक पहचान की धरोहर हैं। उनका सम्मान करते हुए हिंदी को संपर्क भाषा के रूप में अपनाना कोई थोपना नहीं, बल्कि संवाद का एक अवसर हो सकता है।

तमिलनाडु में सरकारी अस्पतालों की पर्चियों और राजमार्गों के संकेत-पट्टों पर हिंदी के इस्तेमाल को लेकर उठे विवाद भी बताते हैं कि भाषा का प्रश्न अक्सर राजनीतिक लाभ-हानि में उलझ जाता है। दूसरी ओर, हिंदी के नाम पर किसी क्षेत्रीय भाषा की उपेक्षा करना भी उचित नहीं है। भारत की ताकत उसकी भाषायी विविधता में है। हिंदी का विकास विरोध से नहीं, सहज स्वीकार्यता और संवाद से होगा। भाषाओं के बीच दीवारें नहीं, संवाद के पुल बनाने होंगे।

भारत की बढ़ती अहमियत

जन जन विचार

...✍ नीरज कुमार दुबे

गुजरात स्थित जामनगर में बुधवार को एक ऐसी मुलाकात हुई, जिसके मायने किसी औद्योगिक दौरे से कहीं ज्यादा बड़े हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो दुनिया की सबसे बड़ी सिंगल-साइट ऑयल रिफाइनरी देखने पहुंचे, जहां रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मुकेश अंबानी तथा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अनंत अंबानी ने उनका स्वागत किया। उनके साथ भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर भी मौजूद रहे। सवाल यह है कि अमेरिका के शीर्ष राजनयिक ने दिल्ली के बजाय जामनगर को इतना महत्व क्यों दिया? जवाब है तेल, ऊर्जा सुरक्षा, वेनेजुएला का भारी कच्चा तेल और अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर बढ़ता दबाव।

हम आपको बता दें कि जामनगर में रुबियो को केवल रिफाइनरी की विशाल मशीनें और अत्याधुनिक तकनीक नहीं दिखाई गई, बल्कि रिलायंस के उस औद्योगिक सामर्थ्य से भी परिचित कराया गया, जिसकी जरूरत आज अमेरिका को भी महसूस हो रही है। कंपनी के मुताबिक, अंबानी ने उन्हें रिफाइनिंग कॉम्प्लेक्स के अलावा निर्माणाधीन डेटा सेंटरों और चरणबद्ध तरीके से शुरू हो रही न्यू एनर्जी गीगा-फैक्ट्रियों की जानकारी दी। बातचीत में पारंपरिक ऊर्जा, नई ऊर्जा, तकनीकी सहयोग, मजबूत सप्लाई चेन और डेटा सेंटरों के लिए भरोसेमंद बिजली की जरूरत जैसे मुद्दे शामिल रहे। यानी चर्चा सिर्फ तेल खरीदने-बेचने की नहीं, बल्कि ऊर्जा और डिजिटल अर्थव्यवस्था के भविष्य की भी थी।

हम आपको बता दें कि जामनगर रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स की संयुक्त कच्चा तेल प्रसंस्करण क्षमता प्रतिदिन 14 लाख बैरल है। इसमें 1999 में शुरू हुई पहली रिफाइनरी और 2008 में चालू हुई निर्यात-केंद्रित दूसरी रिफाइनरी शामिल हैं। रिलायंस के मुताबिक, यह कॉम्प्लेक्स 216 से अधिक प्रकार के कच्चे तेल का प्रसंस्करण कर चुका है। इसकी सबसे बड़ी ताकत भारी और अधिक सल्फर वाले कच्चे तेल को भी उपयोगी पेट्रोलियम उत्पादों में बदलने की क्षमता है।

यही क्षमता इसे अमेरिका के लिए रणनीतिक रूप से अहम बनाती है। वेनेजुएला का भारी कच्चा तेल दुनिया की हर रिफाइनरी आसानी से संसाधित नहीं कर सकती। लेकिन रिलायंस की जामनगर रिफाइनरी इस मामले में विशिष्ट क्षमता रखती है। अमेरिका की वेनेजुएला-केंद्रित तेल रणनीति और वहां से कच्चे तेल की आपूर्ति बढ़ाने की कोशिशों के बीच रिलायंस एक महत्वपूर्ण संभावित साझेदार बनकर उभरी है।

रुबियो ने साफ कहा कि रिलायंस के पास वेनेजुएला समेत पश्चिमी देशों में निकलने वाले भारी कच्चे तेल को रिफाइन करने की खास क्षमता है। यही वजह है कि अमेरिका रिलायंस के साथ मिलकर काम करने के नए रास्ते तलाश रहा है। अनुमानों के मुताबिक, अक्टूबर में रिलायंस हर दिन वेनेजुएला से करीब 3.5 लाख से 3.7 लाख बैरल कच्चा तेल मंगा सकती है। इससे साफ है कि वेनेजुएला के तेल को इस्तेमाल करने की अमेरिकी रणनीति में जामनगर रिफाइनरी की भूमिका बेहद अहम हो सकती है।

इस पूरे घटनाक्रम का दूसरा पहलू अमेरिकी घरेलू अर्थव्यवस्था है। अमेरिका में डीजल की कीमतों में उछाल और ईंधन आपूर्ति को लेकर चिंताओं के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन पर भारी दबाव है। नवंबर में होने वाले मध्यावधि चुनावों से पहले महंगे ईंधन का मुद्दा राजनीतिक रूप से भी संवेदनशील है।

रिलायंस इस तस्वीर में इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जामनगर से डीजल, पेट्रोल और विमानन ईंधन सहित बड़ी मात्रा में रिफाइंड उत्पाद दुनिया भर में भेजे जाते हैं। रिपोर्टों के मुताबिक 2025 की पहली छमाही में जामनगर से 2.166 करोड़ टन रिफाइंड पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात हुआ। इसमें 98.1 लाख टन डीजल, 61.4 लाख टन पेट्रोल और 20.6 लाख टन जेट ईंधन शामिल था। यूरोप इन उत्पादों का सबसे बड़ा क्षेत्रीय बाजार रहा।

साथ ही अमेरिका के लिए रिलायंस की अहमियत सिर्फ उसकी रिफाइनरी तक सीमित नहीं है। भारत में अमेरिकी गैस की बढ़ती मांग भी इसकी बड़ी वजह है। भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर के मुताबिक, पिछले एक साल में भारत के कुल एलपीजी आयात में अमेरिकी गैस की हिस्सेदारी 10 प्रतिशत से बढ़कर 67 प्रतिशत हो गई है। यानी अब भारत को एलपीजी सप्लाई करने वाला अमेरिका सबसे बड़ा देश बन गया है।

इसके अलावा, रुबियो के दौरे के पीछे एक और बड़ा आर्थिक पहलू है। ट्रंप प्रशासन अमेरिका में औद्योगिक उत्पादन और रोजगार वापस लाने की नीति को अपनी प्रमुख उपलब्धियों के रूप में पेश करता रहा है। इसी सिलसिले में टेक्सास के पोर्ट ऑफ ब्राउन्सविल में प्रस्तावित नई तेल रिफाइनरी में रिलायंस की भागीदारी को खास महत्व दिया जा रहा है। अमेरिका में करीब पांच दशकों बाद लगने जा रही इस प्रमुख नई रिफाइनरी पर लगभग 3 से 4 अरब डॉलर खर्च होने का अनुमान है। इसकी सालाना प्रसंस्करण क्षमता करीब 6 करोड़ बैरल अमेरिकी कच्चे तेल की होगी। रिलायंस ने इसके उत्पादन का बड़ा हिस्सा खरीदने के लिए 20 साल का समझौता किया है और इसके 2029 के आसपास परिचालन शुरू करने की उम्मीद है।

रिलायंस की अहमियत का तीसरा पहलू रूस-यूक्रेन युद्ध है। 2022 में युद्ध शुरू होने के बाद भारत रूसी तेल का बड़ा खरीदार बनकर उभरा और रिलायंस ने भी रूसी कच्चे तेल का आयात बढ़ाया। कंपनी के तेल स्रोतों में रूस की हिस्सेदारी 2022 से पहले लगभग 3 प्रतिशत थी, जो 2025 में बढ़कर करीब 50 प्रतिशत तक पहुंच गई। रूसी तेल खरीदने के मुद्दे पर ट्रंप प्रशासन ने भारत पर अतिरिक्त टैरिफ का दबाव बनाया। इसके बाद रिलायंस ने रूसी कच्चे तेल का आयात घटाया। रुबियो ने स्वीकार किया कि भारत अपने ऊर्जा स्रोतों में विविधता ला रहा है, लेकिन रूस से बड़ी मात्रा में तेल खरीदना तुरंत बंद करना आसान नहीं है। उन्होंने भारत को अमेरिका का महत्वपूर्ण साझेदार भी बताया।

उधर, अमेरिकी और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया इस दौरे को सिर्फ एक कारोबारी मुलाकात के तौर पर नहीं देख रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि रिलायंस अमेरिका के कई अहम हितों से जुड़ी हुई है। अमेरिका चाहता है कि भारत रूसी तेल पर अपनी निर्भरता कम करे, वेनेजुएला के तेल का ज्यादा इस्तेमाल हो, ईंधन की कीमतों पर काबू पाया जा सके और अमेरिकी कंपनियों में निवेश बढ़े। इन सभी मुद्दों पर रिलायंस की भूमिका अहम हो सकती है।

दिलचस्प बात यह है कि जहां ट्रंप प्रशासन रिलायंस के साथ ऊर्जा सहयोग बढ़ाने की संभावनाएं तलाश रहा है, वहीं ट्रंप के करीबी एलन मस्क का रिलायंस से टकराव भी सामने आया है। मस्क की कंपनी स्टारलिंक भारत में परिचालन लाइसेंस हासिल करने की कोशिश कर रही है। मस्क ने आरोप लगाया कि भारत में जियो को फायदा पहुंचाने के लिए स्टारलिंक के प्रवेश में बाधाएं डाली जा रही हैं। रिलायंस ने जवाब दिया कि उसे प्रतिस्पर्धा से कभी डर नहीं लगा और वह घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय निवेश एवं नवाचार का स्वागत करने वाले भारत में विकसित हुई है। देखा जाए तो यही विरोधाभास इस पूरे घटनाक्रम को और दिलचस्प बनाता है। अमेरिका के कारोबारी और राजनीतिक हित हर मुद्दे पर एक जैसे नहीं हैं, लेकिन ऊर्जा के मोर्चे पर रिलायंस की क्षमता वॉशिंगटन को उसके साथ बातचीत के लिए प्रेरित कर रही है। कुल मिलाकर देखें तो जामनगर में मार्को रुबियो का दौरा भारत की औद्योगिक ताकत और मुकेश अंबानी के कारोबारी सामर्थ्य का भी बड़ा संकेत है।

बिहार विधान परिषद की 8 सीटों पर मतदान, 5.32 लाख मतदाता करेंगे फैसला

●150 उम्मीदवार मैदान में ●933 केंद्रों पर वोटिंग ●27 अक्टूबर को मतगणना

जन जन विचार
...✍ पटना

बिहार विधान परिषद की स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों की आठ सीटों के लिए शुक्रवार को मतदान होगा। चुनाव प्रचार थमने के बाद अब 5,32,547 मतदाताओं के हाथ में प्रत्याशियों की किस्मत है। कुल 150 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। मतदान सुबह आठ बजे से शाम चार बजे तक होगा, जबकि मतगणना 27 अक्टूबर को निर्धारित है।

इन चुनावों में से स्नातक मतदाताओं की संख्या करीब 4.92 लाख और शिक्षक मतदाताओं की संख्या लगभग 40 हजार है। मतदान के लिए कुल 933 केंद्र बनाए गए हैं। इनमें 598 स्नातक और 335 शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के मतदान केंद्र शामिल हैं। प्रशासन ने शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान के लिए सुरक्षा व्यवस्था तथा निगरानी के इंतजाम किए हैं।

कई सीटों पर दिलचस्प मुकाबला

आठ सीटों के चुनाव में सत्तारूढ़ गठबंधन और विपक्षी दलों के बीच मुकाबले पर राजनीतिक नजरें टिकी हैं। शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों में सारण, पटना, तिरहुत और दरभंगा की सीटें प्रमुख हैं। वहीं स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों में पटना, तिरहुत, दरभंगा और कोसी में प्रत्याशियों के बीच प्रतिस्पर्धा है।

सारण शिक्षक सीट पर जदयू के आनंद पुष्कर, जनसुराज के अफाक अहमद और राजद के जयराम यादव के बीच मुकाबला है। पटना शिक्षक सीट पर भाजपा के नवल किशोर यादव और राजद के डॉ. संजीव कुमार प्रमुख दावेदार हैं। दरभंगा शिक्षक सीट पर कांग्रेस के डॉ. मदन मोहन झा, जदयू के घनश्याम रॉय और राजद के कुमर राऊत के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है।

स्नातक सीटों पर भी राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंकी है। पटना स्नातक सीट पर जदयू के नीरज कुमार के सामने अनुज सिंह और राजद के दिलीप कुमार चुनौती पेश कर रहे हैं। तिरहुत स्नातक सीट पर निर्दलीय बंशीधर ब्रजवासी, जदयू के अभिषेक झा और राजद की डॉ. रश्मि विनायक गौतम के बीच मुकाबला है।

परिणाम पर राजनीतिक दलों की नजर

मतदान के बाद सभी आठ सीटों के उम्मीदवारों का भविष्य मतपेटियों में बंद हो जाएगा। 27 अक्टूबर को मतगणना के साथ तस्वीर साफ होगी।

एमएलसी चुनाव के जरिए व्यवस्था पर लगाम लगा सकते हैं लोग : पीके

वरुण कुमार, मुजफ्फरपुर। जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा है कि बिहार विधान परिषद की स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों की आठ सीटों पर होने वाला चुनाव न तो राज्य सरकार बदलेगा और न ही विपक्ष के नेतृत्व में कोई परिवर्तन करेगा। हालांकि, उन्होंने इसे जनता के लिए बिहार की मौजूदा व्यवस्था के प्रति अपना रुख जाहिर करने का महत्वपूर्ण अवसर बताया। बुधवार को मुजफ्फरपुर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि इस चुनाव में लोग अपने मताधिकार के जरिए व्यवस्था पर लगाम लगाने का संदेश दे सकते हैं।

प्रशांत किशोर ने कहा कि यह चुनाव सरकार बनाने या किसी को सत्ता से हटाने के लिए नहीं है। उनके मुताबिक, बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) की सरकार बनी रहेगी और राजद नेता तेजस्वी यादव विपक्ष के नेता बने रहेंगे। उन्होंने कहा कि विधान परिषद चुनावों के जरिए मतदाता मौजूदा व्यवस्था के प्रति अपनी राय जाहिर कर सकते हैं। उनके बयान को बिहार की राजनीतिक व्यवस्था और सरकार के कामकाज के संदर्भ में जन सुराज के चुनावी रुख के रूप में देखा जा रहा है।

शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाताओं की संख्या सामान्य विधानसभा चुनावों की तुलना में सीमित होती है, लेकिन इन चुनावों के परिणाम राजनीतिक दलों के संगठनात्मक प्रभाव और संबंधित मतदाता वर्गों के बीच उनकी स्वीकार्यता का संकेत दे सकते हैं। प्रशांत किशोर के बयान के बाद इन चुनावों को लेकर राजनीतिक चर्चा तेज होने की संभावना है। हालांकि, चुनाव का वास्तविक प्रभाव मतदाताओं की भागीदारी और परिणामों के सामने आने के बाद ही स्पष्ट होगा।

श्री बाबू की जयंती पर पटना में जुटेंगे लोग, मुजफ्फरपुर से व्यापक भागीदारी की अपील

जन जन विचार
...✍ वरुण कुमार, मुजफ्फरपुर

बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री एवं बिहार केसरी डॉ. श्रीकृष्ण सिंह की जयंती के अवसर पर 25 अक्टूबर को पटना के बापू सभागार में राज्यस्तरीय समारोह आयोजित किया जाएगा। समारोह को सफल बनाने और मुजफ्फरपुर से व्यापक भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शनिवार को गोबरसही स्थित होटल मौर्या के शगुन बैंक्विट हॉल में डॉ. श्रीकृष्ण सिंह जयंती समारोह आयोजन समिति की बैठक हुई। बैठक में पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं राज्यसभा सांसद डॉ. अखिलेश प्रसाद सिंह ने लोगों से बड़ी संख्या में पटना पहुंचकर श्री बाबू को श्रद्धांजलि देने की अपील की।

बैठक में समारोह की तैयारियों, जनभागीदारी और श्री बाबू के विचारों को नई पीढ़ी तक पहुंचाने पर चर्चा हुई। वक्ताओं ने कहा कि डॉ. श्रीकृष्ण सिंह का बिहार के निर्माण, औद्योगिक विकास, शिक्षा और सामाजिक प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उनके कार्यों और विचारों को वर्तमान पीढ़ी तक पहुंचाना समय की आवश्यकता है।

26 वर्षों से जारी है जयंती समारोह की परंपरा

डॉ. अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि डॉ. श्रीकृष्ण सिंह का मुजफ्फरपुर से गहरा संबंध रहा है। वे कई बार तिलक मैदान आए और बिहार के विकास के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए। उन्होंने महेश बाबू के साथ श्री बाबू के प्रगाढ़ संबंधों का भी उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि ललितेश्वर प्रसाद शाही



और पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की प्रेरणा एवं सहयोग से प्रदेश स्तर पर श्री बाबू की जयंती मनाने की परंपरा शुरू हुई थी, जो पिछले 26 वर्षों से लगातार जारी है। उन्होंने इस परंपरा को जीवनपर्यंत आगे बढ़ाने का संकल्प जताया।

डॉ. सिंह ने कहा कि जयंती समारोह केवल श्रद्धांजलि देने का अवसर नहीं, बल्कि नई पीढ़ी को श्री बाबू के ऐतिहासिक योगदान से परिचित कराने का माध्यम भी है। उनके कार्यकाल में बिहार ने उद्योग, शिक्षा और विकास के विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की थी। उन्होंने राज्य में चीनी उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य और औद्योगिक विकास की वर्तमान स्थिति पर चिंता जताते हुए कहा कि बिहार को फिर से विकास की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए महापुरुषों के विचारों से प्रेरणा लेनी चाहिए।

उन्होंने बिहार के विभाजन के दौरान राज्य के हितों की रक्षा के लिए श्री बाबू की भूमिका का उल्लेख किया और मुजफ्फरपुर को उत्तर बिहार के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित करने में उनके योगदान को याद किया।

युवाओं को श्री बाबू के विचारों से जोड़ने पर जोर

बैठक का संचालन कर रहे कांग्रेस नेता धर्मवीर शुक्ला ने कहा कि मुजफ्फरपुर से बड़ी संख्या में लोग पटना पहुंचकर जयंती समारोह को सफल बनाएंगे। उन्होंने कहा कि डॉ. अखिलेश प्रसाद सिंह लगातार श्री बाबू के विचारों और उनके योगदान को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। इस पहल से युवाओं को बिहार के इतिहास और विकास की यात्रा को समझने की प्रेरणा मिलेगी।

नगर के पूर्व विधायक विजेंद्र चौधरी ने कहा कि पिछले 26 वर्षों से डॉ. अखिलेश प्रसाद सिंह के नेतृत्व में श्री बाबू की जयंती मनाई जा रही है। वर्तमान समय में महापुरुषों के विचारों और उनके योगदान को याद करना जरूरी है। उन्होंने भी मुजफ्फरपुर से अधिकाधिक लोगों के पटना पहुंचने की उम्मीद जताई।

विधायक अनिल कुमार ने कहा कि बिहार के निर्माण और विकास में डॉ. श्रीकृष्ण सिंह के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। उनकी उपलब्धियों और विचारों से नई पीढ़ी को परिचित कराना समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है।

डॉ. रश्मि विनायक गौतम के समर्थन की अपील

बैठक में महागठबंधन की प्रत्याशी डॉ. रश्मि विनायक गौतम ने श्री बाबू के आदर्शों पर चलने की बात कही। उन्होंने कहा कि सामाजिक कार्यों के माध्यम से समाज के बीच सक्रिय रहना और महापुरुषों के विचारों को आगे बढ़ाना जरूरी है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि चुनाव में जीत मिलने के बाद भी उनका व्यवहार और सामाजिक कार्यों के प्रति प्रतिबद्धता पहले की तरह बनी रहेगी।

इस अवसर पर डॉ. अखिलेश प्रसाद सिंह ने उपस्थित लोगों से एकजुट होकर डॉ. रश्मि विनायक गौतम के समर्थन में काम करने और उन्हें विजयी बनाने की अपील की।

बैठक में तिरहुत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्याशी संजय सिंह, सतीश कुमार उर्फ मंटन सिंह, सूरज सिंह, अमिताभ शरण, विमल कुमार, रामकिशोर सिंह, अरविंद सिंह, मुखिया अवधेश सिंह, मुरारी शरण उर्फ श्याम बाबू, पूर्व मेयर निसरुद्दीन, शांतनु, सत्यम तिवारी, ललन शुक्ला, विजय चौधरी, डॉ. गौरव वर्मा, सर्वेश रंजन ठाकुर, जूही प्रीतम, डॉ. विनायक गौतम, सुरेश शर्मा, नीरज, मनीष सिंह, वेद प्रकाश, संजय गुप्ता और लोक क्रांति उर्फ चीची यादव सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता एवं समाज के बुद्धिजीवी उपस्थित रहे।

बिहार में डेयरी क्रांति : 50 लाख महिलाएं जुड़ेंगी दुग्ध कारोबार से

जन जन विचार
...✍ पटना



बिहार में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए डेयरी क्षेत्र के विस्तार की तैयारी है। राज्य सरकार का लक्ष्य दुग्ध उत्पादन से जुड़े किसानों की मौजूदा संख्या करीब 12 लाख से बढ़ाकर 50 लाख से अधिक करना है। इस लक्ष्य को हासिल करने में जीविका दीदियों और सुधा सखियों की अहम भूमिका होगी। अब तक करीब सात हजार जीविका दीदियों को पशुपालन और डेयरी प्रबंधन का प्रशिक्षण दिया जा चुका है। ये महिलाएं गांवों में पशुओं की प्राथमिक देखभाल, संतुलित आहार, दुग्ध उत्पादन बढ़ाने और पशुपालकों को जरूरी सेवाओं से जोड़ने का काम करेंगी।

इस पहल के तहत महिलाओं को सुधा सखी, जीविका सुधा बिक्री केंद्रों और दूध संग्रहण केंद्रों से जोड़कर रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराने की योजना है। साथ ही, गांवों में डेयरी उत्पादक सहकारी समितियों के गठन पर भी जोर दिया जा रहा है, ताकि दूध संग्रहण आर विपणन का व्यवस्था मजबूत हो सके।

गांवों में पशुपालकों की मदद करेंगी सुधा सखियां

प्रशिक्षित सुधा सखियां पशुओं के स्वास्थ्य, पोषण और देखभाल से जुड़ी प्राथमिक सेवाएं उपलब्ध कराने में मदद करेंगी। वे पशुपालकों को संतुलित पशु आहार, पशुओं की देखरेख और दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के तरीकों की जानकारी देंगी। जरूरत पड़ने पर पशुपालकों को विशेषज्ञ पशु चिकित्सकों तक पहुंचाने में भी उनकी भूमिका होगी। कृत्रम गभाधान स सबाधत सवाआ के बारे में भी उन्हें प्रशिक्षित किया गया है।

इस व्यवस्था का उद्देश्य पशुपालकों को छोटी-छोटी समस्याओं के लिए दूर के केंद्रों पर निर्भर रहने से राहत देना और गांवों में ही जरूरी जानकारी एवं सहायता उपलब्ध कराना है। इससे पशुओं के स्वास्थ्य में सुधार और दूध उत्पादन में वृद्धि की उम्मीद है।

काम्फेड और जीविका के संयुक्त प्रयास

काम्फेड और जीविका के सयुक्त प्रयासा स सात हजार जीविका दीदियां प्रशिक्षित पशु सखी बन चुकी हैं। अब ये महिलाएं अपने गांवों में स्वयं सहायता समूहों की दूसरी महिला सदस्यों तक भी पशुपालन संबंधी जानकारी पहुंचा रही हैं। इससे ग्रामीण स्तर पर प्रशिक्षित महिला कार्यकर्ताओं का नेटवर्क विकसित करने में मदद मिल रही है।

'सहकार से समृद्धि' की अवधारणा के तहत डेयरी उत्पादक सहकारी समितियों का विस्तार भी इस पहल का अहम हिस्सा है। इसके जरिए दूध उत्पादकों को संगठित करने, दूध संग्रहण की व्यवस्था मजबूत बनाने और विपणन के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने पर जोर दिया जा रहा है।

महिलाओं की आय और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर नजर

डेयरी क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ने से उन्हें अतिरिक्त आय अर्जित करने का अवसर मिल सकता है। वहीं, पशुपालकों को स्थानीय स्तर पर मार्गदर्शन और प्राथमिक सहायता मिलने से पशुपालन की लागत कम करने तथा उत्पादन में सुधार की संभावनाएं बढ़ेंगी।

हालांकि, 50 लाख से अधिक लोगों को दुग्ध कारोबार से जोड़ने का लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रशिक्षण के साथ बाजार तक पहुंच, दूध का उचित मूल्य, पशु चिकित्सा सेवाओं की उपलब्धता और दूध संग्रहण केंद्रों का विस्तार भी जरूरी होगा।

योजना की वास्तविक सफलता इस बात से तय होगी कि ग्रामीण महिलाओं को कितने स्थायी रोजगार मिलते हैं और पशुपालकों की आय में कितना सुधार होता है।

सोनिया गांधी की इंस्टाग्राम पर धमाकेदार एंट्री

जन जन विचार
...✍ नई दिल्ली



कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सोशल मीडिया मंच इंस्टाग्राम पर पदार्पण कर राजनीतिक और डिजिटल जगत का ध्यान खींचा है। गुरुवार को अपना पहला पोस्ट साझा करने के कुछ ही घंटों के भीतर उनके फॉलोअर्स की संख्या एक लाख के पार पहुंच गई। अब तक सोशल मीडिया से अपेक्षाकृत दूरी बनाए रखने वाली सोनिया गांधी ने अपनी आगामी आत्मकथा 'बिलॉनिंग : ए जर्नी ऑफ लव' की झलक के साथ इस मंच पर अपनी शुरुआत की।

अपने पहले पोस्ट में सोनिया गांधी ने लिखा, 'नमस्ते। आज आप सभी के साथ यह पल बांटते हुए मैं दिल से आभारी हूं।' उन्होंने अपनी पुस्तक को प्रेम, कर्तव्य, पीड़ा और अपनेपन की तलाश की कहानी बताया। साथ ही, इसे पाठकों तक पहुंचाने की उत्सुकता भी जाहिर की।

प्रियंका ने मां का मुंह मीठा कराया

सोनिया गांधी ने अपनी पहली पोस्ट के साथ एक वीडियो भी साझा किया, जिसमें प्रकाशक उन्हें पुस्तक की प्रति सौंपते नजर आते हैं। इस अवसर पर उनकी बेटी और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा भी मौजूद थीं। वीडियो में प्रियंका अपनी मां का मुंह मीठा कराती दिखाई देती हैं।

सोनिया गांधी के इंस्टाग्राम पर आने के बाद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं ने भी उनके खाते को अनुसरण करना शुरू कर दिया। कांग्रेस के संचार महासचिव जयराम रमेश ने भी पुस्तक के प्रकाशन की जानकारी साझा की।

10 नवंबर को प्रकाशित होगी आत्मकथा

सोनिया गांधी की आत्मकथा का प्रकाशन 10 नवंबर को हार्परकॉलिन्स इंडिया करेगा। इससे पहले पुस्तक के भारतीय संस्करण को प्रकाशित करने की जिम्मेदारी पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के पास थी, लेकिन पांडुलिपि के कुछ अंशों में संपादन और बदलाव को लेकर विवाद सामने आया। इसके बाद पेंगुइन ने पुस्तक प्रकाशित करने से पीछे हटने का फैसला किया।

बाद में हार्परकॉलिन्स इंडिया ने इस पुस्तक को अपने समय के बहुप्रतीक्षित राजनीतिक संस्मरणों में से एक बताते हुए इसके प्रकाशन की घोषणा की। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कांग्रेस ने सरकार के दबाव और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाए जाने का आरोप लगाया था। हालांकि, इन आरोपों पर विवाद से जुड़े पक्षों के अलग-अलग रुख रहे हैं।

सोनिया गांधी की आत्मकथा को लेकर राजनीतिक हलकों में पहले से ही उत्सुकता रही है। ऐसे में इंस्टाग्राम पर उनकी शुरुआत और पुस्तक की पहली झलक ने इसके प्रति लोगों की दिलचस्पी और बढ़ा दी है। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि आत्मकथा में उनके राजनीतिक जीवन, व्यक्तिगत अनुभवों और भारतीय राजनीति के अहम घटनाक्रमों को किस तरह प्रस्तुत किया गया है। सोशल मीडिया पर उनकी यह शुरुआत कांग्रेस नेतृत्व के लिए युवा पीढ़ी तक पहुंचने का एक नया माध्यम भी बन सकती है। हालांकि, पहले ही दिन बड़ी संख्या में फॉलोअर्स जुड़ना अपने आप में लोकप्रियता का संकेत है, लेकिन इससे राजनीतिक प्रभाव में होने वाले किसी बदलाव का निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी।

वैशाली में सड़क हादसे में तीन किशोर दोस्तों की मौत, गांव में मातम

महुआ। वैशाली जिले के महुआ में महुआ-ताजपुर मार्ग पर निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार तीन किशोरों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान अभिषेक कुमार उर्फ भोला, अमन कुमार और प्रीतम कुमार के रूप में हुई है। तीनों नवमी के दिन गोविंदपुर सिंघाड़ा मेला देखकर घर लौट रहे थे। हादसे में अभिषेक और अमन की मौत रास्ते में ही हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल प्रीतम ने करीब 20 घंटे बाद दम तोड़ दिया। तीनों किशोर दसवीं और नौवीं कक्षा के छात्र थे। घटना के बाद महुआ नगर परिषद के वार्ड संख्या 16 स्थित सिंह राय गांव के पश्चिमी टोले में शोक की लहर है। त्योहारों की तैयारियों के बीच तीन परिवारों में मातम पसरा है। हादसे के बाद अज्ञात वाहन चालक मौके से फरार हो गया।

तीसरी बार विश्व विजेता बनने उतरेंगी भारतीय बेटियां

जन जन विचार
...✍ नई दिल्ली

अंडर-19 महिला टी-20 विश्व कप 2027

- भारत का पहला मुकाबला वेस्टइंडीज से
- बांग्लादेश और नेपाल करेंगे संयुक्त मेजबानी

भारतीय महिला क्रिकेट की नई पीढ़ी एक बार फिर विश्व क्रिकेट में अपनी बादशाहत साबित करने के इरादे से मैदान में उतरेगी। आईसीसी अंडर-19 महिला टी-20 विश्व कप 2027 में भारतीय टीम अपने खिताब की रक्षा करने के साथ लगातार तीसरी बार विश्व चैंपियन बनने का लक्ष्य लेकर उतरेगी। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) द्वारा घोषित कार्यक्रम के अनुसार, भारत का पहला मुकाबला 22 जनवरी 2027 को नेपाल के कीर्तिपुर स्थित टीयू इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में वेस्टइंडीज से होगा।

खिताबी हैट्रिक पर भारत की नजर

भारतीय अंडर-19 महिला टीम ने 2023 में दक्षिण अफ्रीका में आयोजित पहले विश्वकप का खिताब जीता था। इसके बाद 2025 में मलेशिया में भी भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए खिताब अपने नाम किया। अब 2027 में भारत के सामने लगातार तीसरी बार ट्रॉफी जीतकर इतिहास रचने की चुनौती होगी।

पिछले संस्करण में निकी प्रसाद की कप्तानी वाली भारतीय टीम ने फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को हराकर अपनी प्रतिभा और दबाव में बेहतर प्रदर्शन करने की क्षमता का परिचय दिया था। इस बार भी भारतीय टीम से काफी उम्मीदें होंगी, हालांकि खिताब बचाने की राह आसान नहीं रहने वाली।

नेपाल में भारत की शुरुआती परीक्षा

भारत को ग्रुप-ए में वेस्टइंडीज, आयरलैंड और मेजबान नेपाल के साथ रखा गया है। भारतीय टीम 22 जनवरी को वेस्टइंडीज के खिलाफ अभियान शुरू करेगी। इसके बाद 24 जनवरी को नेपाल और 26 जनवरी को आयरलैंड से मुकाबला होगा।

नेपाल के घरेलू मैदान पर खेलने से मेजबान टीम को दर्शकों का समर्थन मिलेगा। ऐसे में भारत के लिए शुरुआती मुकाबले महत्वपूर्ण होंगे। ग्रुप चरण में लगातार अच्छे प्रदर्शन से ही सुपर सिक्स में जगह बनाने और खिताब की ओर आगे बढ़ने का रास्ता मजबूत होगा।

16 टीमें, 41 मुकाबले

टूर्नामेंट में कुल 16 टीमें हिस्सा लेंगी और 41 मैच खेले जाएंगे। बांग्लादेश और नेपाल संयुक्त रूप से प्रतियोगिता की मेजबानी करेंगे। कार्यक्रम के अनुसार, मुकाबले चटगांव, सिलहट और काठमांडू के निर्धारित स्थलों पर होंगे।

ग्रुप चरण 21 से 26 जनवरी तक चलेगा। इसके बाद टीमें सुपर सिक्स चरण में पहुंचेंगी, जहां से शीर्ष प्रदर्शन करने वाली टीमें सेमीफाइनल में जगह बनाएंगी। दोनों सेमीफाइनल 4 फरवरी को चटगांव में खेले जाने निर्धारित हैं। फाइनल 6 फरवरी को होगा, जबकि 7 फरवरी को आरक्षित दिन रखा गया है।

नई प्रतिभाओं के लिए बड़ा मंच

अंडर-19 विश्वकप युवा खिलाड़ियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने का महत्वपूर्ण अवसर है। यहां प्रदर्शन करने वाली खिलाड़ियों के लिए भविष्य में सीनियर राष्ट्रीय टीम तक पहुंचने की संभावनाएं मजबूत हो सकती हैं। साथ ही, यह प्रतियोगिता एशिया में महिला क्रिकेट की लोकप्रियता और विकास को भी बढ़ावा दे सकती है।

भारतीय टीम के सामने अब चुनौती केवल पिछले दो खिताबों की सफलता दोहराने की नहीं, बल्कि नई प्रतिभाओं के दम पर विश्व क्रिकेट में अपना दबदबा बनाए रखने की भी है। क्या भारतीय बेटियां 2027 में खिताबी हैट्रिक पूरी कर पाएंगी? इसका जवाब मैदान पर उनके प्रदर्शन से मिलेगा।

वैभव को लगातार बेंच पर बैठाने को लेकर उठ रहे सवाल

जन जन विचार
...✍ नई दिल्ली

भारतीय क्रिकेट के उभरते सितारे वैभव सूर्यवंशी को लगातार अंतिम एकादश से बाहर रखने का मामला अब चर्चा का विषय बन गया है। वेस्टइंडीज के खिलाफ टी-20 श्रृंखला में अवसर नहीं मिलने के बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टी-20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में भी उन्हें खेलने का मौका नहीं मिला। 22 अक्टूबर को क्राइस्टचर्च में खेले गए मुकाबले के लिए भारतीय टीम ने दो बदलाव किए, लेकिन 15 वर्षीय वैभव को फिर बाहर ही रखा। इससे युवा प्रतिभा को अवसर देने और टीम के स्थापित खिलाड़ियों पर भरोसा बनाए रखने के बीच संतुलन को लेकर बहस तेज हो गई है।

भारतीय टी-20 कप्तान श्रेयस अय्यर ने वैभव को लगातार अवसर नहीं मिलने पर कहा है कि युवा बल्लेबाज को अभी इंतजार करना होगा। उन्होंने संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा की सलामी जोड़ी के लगातार अच्छे प्रदर्शन का हवाला देते हुए स्पष्ट किया कि वैभव को फिलहाल सीधे अंतिम एकादश में जगह नहीं दी जा सकती।

अय्यर के मुताबिक, वैभव अभी काफी युवा हैं और उनके पास आगे अवसर हासिल करने के लिए पर्याप्त समय है। टीम प्रबंधन चाहता है कि वह खिलाड़ियों के साथ रहते हुए अनुभव हासिल करें और विदेशी परिस्थितियों को समझें।

वैभव ने अब तक आठ टी-20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में 246 रन बनाए हैं। उनका स्ट्राइक रेट 186.36 रहा है और उनके नाम दो अर्धशतक भी हैं। कम उम्र में तेज बल्लेबाजी की क्षमता ने उन्हें भारतीय क्रिकेट के सबसे चर्चित युवा खिलाड़ियों में शामिल किया है।

आईपीएल में भी उनके प्रदर्शन ने काफी ध्यान खींचा है। हालांकि, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में चयन केवल व्यक्तिगत प्रतिभा पर निर्भर नहीं करता। टीम संयोजन, विपक्षी गेंदबाजी, पिच की परिस्थितियां और मौजूदा खिलाड़ियों का प्रदर्शन भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

वैभव को लगातार बाहर रखे जाने पर क्रिकेट प्रेमियों के बीच यह सवाल उठ रहा है कि जब किसी युवा खिलाड़ी को राष्ट्रीय टीम में शामिल किया जाता है, तो उसे अपनी क्षमता साबित करने के पर्याप्त अवसर कब मिलेंगे। दूसरी ओर, टीम प्रबंधन का तर्क है कि लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही सलामी जोड़ी को बदलना फिलहाल जरूरी नहीं है।

यह भी ध्यान रखना होगा कि वैभव का करियर अभी शुरुआती दौर में है। टीम के साथ रहकर अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों को समझना उनके लिए उपयोगी हो सकता है, लेकिन मैदान पर खेलने का अनुभव भी उतना ही महत्वपूर्ण है।

फिलहाल चयनकर्ताओं और टीम प्रबंधन ने स्थापित सलामी जोड़ी पर भरोसा बनाए रखा है। अब निगाहें न्यूजीलैंड के खिलाफ आगामी मुकाबलों पर हैं। देखना होगा कि वैभव को इस श्रृंखला में अवसर मिलता है या उन्हें अभी और इंतजार करना पड़ता है।

पृष्ठ 1 का शेषांश...

फ्रांस की सड़कों पर ...

5.5 लाख लोग सड़कों पर उतरे, जबकि प्रदर्शन आयोजकों ने यह संख्या करीब आठ लाख बताई। पेरिस, मार्सेय, लियोन और बोर्डो सहित कई शहरों में शांतिपूर्ण मार्च के बीच कुछ समूहों ने दुकानों में लूटपाट की, सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया और पुलिस के साथ संघर्ष किया। लिमोज में ऐतिहासिक नगर भवन भी आग की चपेट में आया।

फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने हिंसा की निंदा करते हुए शांति की अपील की। रिपोर्ट के मुताबिक अधिकारियों ने देशभर में लगभग 2,400 लोगों को गिरफ्तार किए जाने की जानकारी दी। हिंसा के दौरान एक प्रदर्शनकारी की मौत भी हुई। इन घटनाओं ने प्रशासन की तैयारी, खुफिया आकलन और भीड़ नियंत्रण की क्षमता पर सवाल खड़े किए हैं।

लेकिन इस पूरे घटनाक्रम को केवल उपद्रवियों की करतूत बताकर खारिज कर देना भी समस्या की पूरी तस्वीर नहीं दिखाता। फ्रांस में स्कूलों में शिक्षकों की कमी, जर्जर सुविधाओं, शिक्षा व्यवस्था की समस्याओं और बढ़ती महंगाई के खिलाफ छात्रों का आंदोलन पहले से चल रहा था। बाद में मजदूर संगठनों और दूसरे समूहों के जुड़ने से असंतोष का दायरा व्यापक हो गया।

महंगाई का असर केवल आंकड़ों में नहीं, बल्कि आम परिवारों की रोजमर्रा की जिंदगी में दिखाई देता है। जब आय की तुलना में भोजन, परिवहन, ईंधन, किराया और शिक्षा पर खर्च तेजी से बढ़ता है, तो आर्थिक असुरक्षा सामाजिक असंतोष में बदल सकती है। युवाओं के लिए रोजगार, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और किफायती आवास की उपलब्धता भी बड़ी चिंता बनती जा रही है। फ्रांस में छात्रों का गुस्सा केवल कक्षाओं और शिक्षकों तक सीमित नहीं रहा। आंदोलन के साथ जीवन-यापन की लागत, सार्वजनिक सेवाओं और सामाजिक असमानता के सवाल भी जुड़ गए। सरकार के लिए चुनौती यह है कि वह हिंसा पर नियंत्रण के साथ-साथ उन शिकायतों का समाधान भी करे, जिन्होंने इतने बड़े वर्ग को सड़कों पर उतरने के लिए प्रेरित किया।

यूरोप के दूसरे हिस्सों में असंतोष के कारण अलग-अलग हैं, लेकिन आम नागरिकों की बुनियादी जरूरतें कई जगह एक जैसी चुनौती बन रही हैं।

स्पेन और पुर्तगाल में आवास की बढ़ती कीमतें तथा महंगे किराये युवाओं और मध्यमवर्गीय परिवारों पर दबाव डाल रहे हैं। इटली में वेतन, महंगाई, स्वास्थ्य सेवाओं और रोजगार से जुड़े सवालों ने विरोध प्रदर्शनों को हवा दी है। अल्बानिया में भ्रष्टाचार के आरोपों और सार्वजनिक सेवाओं को लेकर सरकार विरोधी आंदोलन देखने को मिले हैं। यूरोप के विभिन्न देशों में चल रहे प्रदर्शनों के पीछे महंगाई, आवास संकट, शिक्षा और सार्वजनिक सेवाओं को लेकर असंतोष प्रमुख कारणों में शामिल हैं। हालांकि हर देश की राजनीतिक परिस्थितियां अलग हैं; इसलिए सभी आंदोलनों को एक ही कारण या एक ही राजनीतिक विचारधारा से जोड़ना उचित नहीं होगा।

अमिताभ बच्चन को डॉक्टरों ने दी आराम की सलाह, काम से लेंगे छोटा विराम

जन जन विचार
...✍ नई दिल्ली



सदी के महानायक अमिताभ बच्चन को डॉक्टरों ने कुछ दिनों तक आराम करने और स्वास्थ्य लाभ लेने की सलाह दी है। 84 वर्षीय अभिनेता ने बुधवार को सोशल मीडिया मंच एक्स पर इसकी जानकारी देते हुए अपने प्रशंसकों से माफी मांगी। उन्होंने संकेत दिया कि आराम के इस दौर में वह सोशल मीडिया पर भी पहले की तरह सक्रिय नहीं रह पाएंगे। हालांकि, उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि डॉक्टरों ने उन्हें आराम करने की सलाह किस वजह से दी है।

अमिताभ बच्चन ने हिंदी में लिखे अपने संदेश में कहा, 'क्षमा चाहता हूं। माफी मांगता हूं। मुझे आराम करने और स्वस्थ होने के लिए कुछ दिन का अवकाश लेने की सलाह दी गई है। इसलिए फिलहाल कुछ लिख पाने में असमर्थ हूं।' उनके इस संदेश के बाद प्रशंसकों के बीच उनके स्वास्थ्य को लेकर चर्चा शुरू हो गई है।

'कौन बनेगा करोड़पति' के सेट पर लगी थी चोट

इस महीने की शुरुआत में अमिताभ बच्चन ने लोकप्रिय टेलीविजन कार्यक्रम 'कौन बनेगा करोड़पति-18' की एक कड़ी की शुरुआत करते हुए बताया था कि पिछले दिन की शूटिंग के दौरान उनके घुटने में चोट लग गई थी। उन्होंने अपने बाएं घुटने की ओर इशारा करते हुए कहा था कि सेट पर गिरने के कारण उन्हें परेशानी हुई।

चोट के बावजूद उन्होंने कार्यक्रम की शूटिंग जारी रखी। हालांकि, शुरुआती संबोधन के दौरान वह अपनी चिर-परिचित ऊर्जा के साथ मंच पर सक्रिय नजर नहीं आए और कुछ समय तक बैठे रहे। बाद में वह खड़े होकर प्रतियोगियों के साथ कार्यक्रम का संचालन करते दिखाई दिए।

सेहत और संन्यास की अटकलों पर पहले भी दी थी सफाई

अमिताभ बच्चन की सेहत को लेकर इससे पहले भी कई तरह की चर्चाएं सामने आ चुकी हैं। पिछले महीने उनके एक रहस्यमय ब्लॉग संदेश के बाद अभिनय से संन्यास लेने की अटकलें लगने लगी थीं। हालांकि, बाद में उन्होंने स्पष्ट किया था कि उनका संदेश अभिनय की दुनिया से विदाई का संकेत नहीं था।

इस साल मई में भी उनके मुंबई स्थित नानावटी अस्पताल जाने की खबरें आई थीं। उस समय सामने आई रिपोर्टों के अनुसार, वह नियमित स्वास्थ्य जांच के लिए अस्पताल गए थे और उसी दिन घर लौट आए थे।

'कल्कि 2898 एडी' के अगले भाग में आएंगे नजर

कामकाज की बात करें तो अमिताभ बच्चन फिलहाल 'कौन बनेगा करोड़पति' के मौजूदा सत्र से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा वह निर्देशक नाग अश्विन की फिल्म 'कल्कि 2898 एडी' के अगले भाग में अश्वत्थामा की भूमिका में नजर आएंगे। इस फिल्म में प्रभास और कमल हासन भी अहम भूमिकाओं में दिखाई देंगे।

फिलहाल अभिनेता ने अपने स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या के बारे में विस्तृत जानकारी नहीं दी है। ऐसे में उनके आराम पर जाने को लेकर किसी गंभीर बीमारी या अभिनय से लंबे विराम का निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा। उनके प्रशंसक अब उनके जल्द स्वस्थ होकर काम पर लौटने की उम्मीद कर रहे हैं।

पिता यानि बाबू अपना नाम माटी में मरा देता है।

मौन रहता पिता रास्ता समझाता ।
संगत का द्वार यथा निभाता।।
पिता यानि बापू की जिंदगी।
निस्वार्थ सच्चे प्रेम से परिवार का कर्तव्य निभाता।
माँ की तरह प्यार और अपनापन नहीं दिखाता!
शांत और कम बातें दिखाता, पर
जिम्मेदारियों से मजबूती का आँगन चमकाता।
बापू, कुछ कहता नहीं, पर अच्छे-बुरे की पहचान सीखा देता।
अनमोल प्रतीक है पिता की पहचान
सिखाता सही मार्ग ,सही विषयों की पहचान
संगत से भटकते को प्रेम से समझाता।
प्रेम के साथ , कठोरता से भी गलतियों को सुधारता
बाबू, अपने बच्चों की भलाई निभाता।
खुद के सपने, खुद की इच्छाओं को मिटाता!
बच्चों के उपहार, सपने, खुशी का द्वार चमकाता।
मुश्किल की कमजोरी को सुधारता
ये पिता, सिर्फ और सिर्फ पिता ही
चिंताओं में भी मुस्कान के साथ हल्की मुस्कुराहट दिखाता।
घर आँगन में बच्चों की मुस्कान देखते ही पिता खुश हो जाता ।
वास्तव में बेटे-बेटियों की असली दोस्त/सखा
माता-पिता ही असली दोस्त सही रिश्तों के द्वार चमकाता।
पिता यानि बाबू की जिंदगी का असली द्वार, बच्चों की सफलता का द्वार है।
वही-वही बापू यानि पिता
जब अनजाने में ही बच्चों के मार्ग में गलत व्यवहार,गलत संगत,गलत चरित्र को अपनाले तो!!!!
को देख लेते हैं, पिता की असली मौत तो बेमौत हो जाती है!!!!!
पिता यानि बाबू अपना नाम माटी में मरा देता है।

-सुश्री रजनी देवी शर्मा, दाधिच

मंगल के रहस्यों की तलाश में जापान, फोबोस से धरती पर आएगी दूसरे ग्रह की मिट्टी

जन जन विचार
...✍ नई दिल्ली



अंतरिक्ष की दुनिया में अब एक ऐसी खोज की तैयारी है, जो मंगल ग्रह के अतीत को समझने की दिशा में नई खिड़की खोल सकती है। जापान की अंतरिक्ष एजेंसी जाक्सा अपने महत्वाकांक्षी 'मार्टियन मून्स एक्सप्लोरेशन' (एमएमएक्स) मिशन के जरिए मंगल के चंद्रमा फोबोस की मिट्टी के नमूने पृथ्वी पर लाने की तैयारी कर रही है। यह मिशन केवल किसी दूसरे खगोलीय पिंड से मिट्टी लाने का अभियान नहीं है, बल्कि मंगल के इतिहास, उसके चंद्रमाओं के जन्म और सौरमंडल के शुरुआती दौर को समझने की एक बड़ी वैज्ञानिक कोशिश भी है।

योजना के अनुसार, अंतरिक्ष यान फोबोस तक पहुंचेगा, उसकी सतह का अध्ययन करेगा और वहां से नमूने एकत्र करने के बाद उन्हें पृथ्वी पर वापस लाएगा। नमूनों से भरा कैप्सूल वर्ष 2031 में ऑस्ट्रेलिया में उतरने की योजना के तहत तैयार किया जा रहा है। यदि मिशन सफल रहता है, तो वैज्ञानिकों को फोबोस की मिट्टी का प्रयोगशालाओं में विस्तृत विश्लेषण करने का अवसर मिलेगा।

फोबोस आखिर है क्या?

मंगल के दो प्राकृतिक उपग्रह हैं-फोबोस और डीमोस। पृथ्वी के चंद्रमा के विपरीत, ये दोनों आकार में बहुत छोटे और अनियमित आकृति वाले हैं। फोबोस मंगल के अधिक निकट है और उसके चारों ओर बहुत तेजी से परिक्रमा करता है। इसकी सतह पर अनेक गड्ढे हैं, जो लंबे समय से अंतरिक्ष में उल्कापिंडों और अन्य पिंडों के प्रभावों का संकेत देते हैं।

फोबोस को लेकर वैज्ञानिकों के सामने एक बुनियादी सवाल है- क्या यह कभी मंगल से अलग हुए पदार्थों से बना था या फिर कोई क्षुद्रग्रह था, जिसे मंगल ने अपने गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से अपने आसपास की कक्षा में बांध लिया?

पहली संभावना के अनुसार, किसी विशाल टक्कर के दौरान मंगल से निकले पदार्थों ने मिलकर उसके चंद्रमाओं का निर्माण किया होगा। दूसरी संभावना यह है कि ये पिंड सौरमंडल में पहले से मौजूद थे और बाद में मंगल के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में आ गए। फोबोस से प्राप्त नमूनों की संरचना, खनिजों और रासायनिक गुणों का अध्ययन इन दोनों संभावनाओं के बीच अंतर समझने में मदद कर सकता है।

मिट्टी में छिपा है मंगल के अतीत का सुराग

एमएमएक्स मिशन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा फोबोस की सतह से मिट्टी के नमूने एकत्र करके पृथ्वी पर लाना है। मिशन की योजना के अनुसार, सतह से लगभग दो सेंटीमीटर नीचे तक के पदार्थ के नमूने जुटाने और कम से कम 10 ग्राम सामग्री पृथ्वी पर लाने का लक्ष्य रखा गया है।



ৰাইজৰ কথা ৰাইজৰ মাজলৈ

সাপ্তাহিক

জন জন বিচাৰ

৯

Guwahati, 23 October, 2026 Friday :: শুক্রবাৰ, আহিন, শুক্ল পক্ষ, দ্বাদশী, শকাব্দ ১৯৪৮

‘চীনা’ বুলি উপহাস ত্রিপুৰাৰ যুৱকক, কেতিয়া বন্ধ হ’ব উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ মানুহক লৈ বৰ্ণবিদ্বেষী ঠাট্টা ?

জন জন বিচাৰ
...নতুন দিল্লী

ভাৰতৰ নাগৰিক হৈও উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ মানুহে নিজৰ ভাৰতীয় পৰিচয় বাৰে বাৰে প্ৰমাণ কৰিবলগীয়া হ’ব নেকি ? মুখমণ্ডল, চকুৰ গঠন অথবা শাৰীৰিক বৈশিষ্ট্যৰ বাবে কোনো এজন ব্যক্তিক ‘বিদেশী’ বা ‘চীনা’ বুলি উপহাস কৰাৰ অধিকাৰ কাৰো আছে নেকি ? দিল্লীৰ এগৰাকী ছ’চিয়েল মিডিয়া কনটেণ্ট ক্ৰিয়েটৰ আমিৰ শ্ৱকীনে ত্রিপুৰাৰ এজন যুৱকক লক্ষ্য কৰি কৰা বুলি অভিযোগ উঠা বৰ্ণবিদ্বেষী মন্তব্যক কেন্দ্ৰ কৰি এই প্ৰশ্নবোৰ পুনৰ সম্মুখলৈ আহিছে। ভাইৰেল ভিডিঅ’টোক লৈ ত্রিপুৰাকে ধৰি উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ বিভিন্ন মহলত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। ঘটনাটোৰ তদন্তৰ বাবে দিল্লী আৰু ত্রিপুৰা আৰক্ষী সক্ৰিয় হোৱাৰ লগতে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজুৰেও কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ পোষকতা কৰিছে।

বিতৰ্কৰ কেন্দ্ৰবিন্দুত থকা ভিডিঅ’টোত ত্রিপুৰাৰ যুৱকজনৰ চেহেৰা আৰু পৰিচয়ক লৈ আপত্তিজনক মন্তব্য কৰা হোৱা বুলি অভিযোগ উঠিছে। ঘটনাটোৱে কেৱল এজন যুৱকৰ অপমানৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰা নাই; ৰবং উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ মানুহৰ প্ৰতি সমাজৰ একাংশৰ মাজত আজিও বৰ্তি থকা বৰ্ণবিদ্বেষী মানসিকতাকো উদঙাই দিছে।

‘ভিডিঅ’টো পৰিকল্পিত আছিল’-ক্ষমা বিচাৰি যুক্তি আমিৰৰ

বিতৰ্ক তীব্ৰ হোৱাৰ পিছত আমিৰ শ্ৱকীনে ক্ষমা বিচাৰি ভিডিঅ’টো পৰিকল্পিত বা স্ক্ৰিপ্টেড আছিল বুলি দাবী কৰিছে। তেওঁৰ মতে, ভিডিঅ’টোত দেখা যোৱা যুৱকজন তেওঁৰ চিনাকি আৰু সমগ্ৰ কথোপকথন হাস্যৰসৰ উদ্দেশ্যে প্ৰস্তুত কৰা হৈছিল। কাৰো অনুভূতিত আঘাত দিয়াৰ উদ্দেশ্য নাছিল বুলিও তেওঁ দাবী কৰে।

কিন্তু এই যুক্তিয়ে মূল প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ দিব পৰা নাই। কোনো ভিডিঅ’ পৰিকল্পিত হ’লেই তাত ব্যৱহাৰ কৰা বৰ্ণবিদ্বেষী শব্দ গ্ৰহণযোগ্য হৈ পৰেনে ? কোনো ব্যক্তি চিনাকি হ’লেই তেওঁৰ শাৰীৰিক বৈশিষ্ট্যক লৈ অপমানজনক মন্তব্য কৰাৰ অধিকাৰ লাভ কৰিব পাৰিনে ? আৰু এজন ব্যক্তিক লক্ষ্য কৰি কৰা ঠাট্টাই যদি এটা সম্পূৰ্ণ জনগোষ্ঠীৰ পৰিচয়ক অপমান কৰে, তেন্তে তাক কেৱল মনোৰঞ্জনৰ নামত উপেক্ষা কৰা উচিতনে ?

হাস্যৰস আৰু অপমানৰ মাজত স্পষ্ট পাৰ্থক্য আছে। কাৰোবাৰ পৰিচয়ক হেয় প্ৰতিপন্ন কৰি সামাজিক মাধ্যমত জনপ্ৰিয়তা অৰ্জনৰ চেষ্টা কৰা হ’লে, তাৰ সামাজিক পৰিণামৰ বিষয়েও প্ৰশ্ন উঠিবই।



দিল্লী-ত্রিপুৰা আৰক্ষীৰ তদন্ত

ঘটনাটোক লৈ দিল্লীৰ সদৰ বজাৰ থানাত ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতাৰ ১৯২, ১৯৬, ৩৫২ আৰু ৩৫৩ নম্বৰ ধাৰাৰ অধীনত গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে বুলি প্ৰকাশিত প্ৰতিবেদনত উল্লেখ কৰা হৈছে। তদন্তত দিল্লী আৰক্ষীৰ ইণ্টেলিজেন্স ফিউজন এণ্ড ষ্ট্ৰেটেজিক অপাৰেচনছ শাখাইও কাৰিকৰী সহায় আগবঢ়াইছে।

আনহাতে, ত্রিপুৰা আৰক্ষীয়েও গোচৰ ৰুজু কৰি দিল্লী আৰক্ষীৰ সৈতে সমন্বয় স্থাপনৰ বাবে বিশেষ দল প্ৰেৰণ কৰিছে। ত্রিপুৰাৰ আৰক্ষী সঞ্চালকপ্ৰধান জি এছ ৰাৰে অভিযুক্ত আৰু ভুক্তভোগীৰ পৰিচয় চিনাক্ত কৰা হৈছে বুলি জানিবলৈ দিয়াৰ লগতে আইন অনুসৰি ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ কথা উল্লেখ কৰিছে।

ত্রিপুৰা ষ্টুডেণ্টছ ফ’ৰাম দিল্লীয়েও চৰ অক্টোবৰত সংশ্লিষ্ট আৰক্ষী বিষয়াৰ ওচৰত অভিযোগ দাখিল কৰি নিৰপেক্ষ তদন্তৰ দাবী জনাইছে। ভিডিঅ’টোৰ মূল ৰেকৰ্ডিং, মেটাডাটা, একাউণ্টৰ তথ্য আৰু আপলোডৰ ইতিহাস সংৰক্ষণ কৰাৰ লগতে ভুক্তভোগী যুৱকজনক সম্ভাব্য ভাবুকি আৰু হাৰাশাস্তিৰ পৰা সুৰক্ষা দিয়াৰো দাবী উত্থাপন কৰা হৈছে। যুৱ টিপ্ৰা ফেডাৰেচন আৰু টিপ্ৰা ইণ্ডিজেনাছ ষ্টুডেণ্টছ ফেডাৰেচনেও পৃথকে অভিযোগ দাখিল কৰিছে বুলি প্ৰতিবেদনত প্ৰকাশ পাইছে।

কিৰেণ ৰিজিজুৰ কঠোৰ বার্তা ৰাজনৈতিক প্ৰতিক্ৰিয়া

কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজুৱে ঘটনাটোৰ প্ৰতি কঠোৰ স্থিতি গ্ৰহণ কৰি অভিযুক্তৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ পোষকতা কৰিছে। ত্রিপুৰাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মাণিক সাহাইও ৰাজ্যৰ আৰক্ষী সঞ্চালকপ্ৰধানক দিল্লী আৰক্ষীৰ সৈতে সমন্বয় কৰি উপযুক্ত ব্যৱস্থা নিশ্চিত কৰিবলৈ নির্দেশ দিছে।

টিপ্ৰা মথাৰ প্ৰতিষ্ঠাপক প্ৰদ্যোৎ কিশোৰ মাণিক্য দেববর্মাকে ধৰি বিভিন্ন নেতাই ঘটনাটোৰ নিন্দা কৰিছে। ইফালে, বিজেপিৰ ত্রিপুৰা গোটে আমিৰ শ্ৱকীনক কংগ্ৰেছৰ কর্মী বুলি দাবী কৰি কংগ্ৰেছক লক্ষ্য কৰি সমালোচনা কৰিছে। অৱশ্যে, এই ৰাজনৈতিক অভিযোগ আৰু প্ৰত্যাবোপৰ মাজতো ঘটনাটোৰ মূল বিষয়টো হৈছে-অভিযোগৰ নিৰপেক্ষ তদন্ত আৰু উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ মানুহৰ মর্যাদা সুৰক্ষিত কৰা।

উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ মানুহৰ ভাৰতীয় পৰিচয়ক লৈ প্ৰশ্ন কিয় ?

এই ঘটনাই পুনৰ প্ৰমাণ কৰিছে যে বৰ্ণবিদ্বেষ কেৱল কোনো এজন ব্যক্তিৰ বিৰুদ্ধে কৰা মন্তব্যতে সীমাবদ্ধ নাথাকে। এনে মন্তব্যৰ আঁৰত যদি কোনো জনগোষ্ঠীৰ শাৰীৰিক বৈশিষ্ট্যক লৈ থকা পূৰ্বধাৰণা আৰু অৱজ্ঞা থাকে, তেন্তে তাৰ প্ৰভাৱ বৃহত্তৰ সমাজলৈ বিয়পি পৰে। উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ মানুহক চেহেৰাৰ ভিত্তিত ‘চীনা’ বুলি কোৱা, তেওঁলোকৰ ভাষা-সংস্কৃতিক লৈ ঠাট্টা কৰা অথবা তেওঁলোকক ভাৰতৰ বাহিৰৰ মানুহৰ দৰে ব্যৱহাৰ কৰাটো কোনো নির্দোষ ধেমালি নহয়। ভাৰতীয় সংবিধানে সকলো নাগৰিককে সমতা আৰু মর্যাদাৰ অধিকাৰ প্ৰদান কৰিছে। এই অধিকাৰ কোনো অঞ্চলৰ মানুহৰ বাবে কম বা আনৰ বাবে অধিক হ’ব নোৱাৰে। আইনে অভিযুক্তৰ দোষ নির্ধাৰণ কৰিব আৰু সেই অধিকাৰ আদালতৰ। কিন্তু সামাজিক দায়বদ্ধতাৰ প্ৰশ্নটো তাৰ পৰা পৃথক। সামাজিক মাধ্যমত অনুসৰণকাৰী বৃদ্ধি বা জনপ্ৰিয়তা অর্জনৰ প্ৰতিযোগিতাই যদি মানুহৰ পৰিচয় আৰু সম্মানক আঘাত কৰে, তেন্তে সমাজে সেই প্ৰৱণতাৰ বিৰুদ্ধে স্পষ্ট স্থিতি ল’ব লাগিব। উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চল ভাৰতৰ প্ৰান্ত নহয়, ভাৰতৰ অবিচ্ছেদ্য অংশ। এই অঞ্চলৰ মানুহৰ সম্মান কোনো অনুগ্ৰহ নহয়, তেওঁলোকৰ অধিকাৰ। আমিৰ শ্ৱকীনক কেন্দ্ৰ কৰি সৃষ্টি হোৱা বিতৰ্কৰ পৰা এটাই শিক্ষা লোৱা উচিত-ক্ষমা বিচৰাটো প্ৰয়োজনীয় হ’ব পাৰে, কিন্তু বৰ্ণবিদ্বেষী মানসিকতাৰ পৰিৱর্তন, নিৰপেক্ষ তদন্ত আৰু দায়বদ্ধতা নিশ্চিত কৰাটো তাৰো অধিক গুৰুত্বপূৰ্ণ।

ফ্রেঞ্চ অ'পেনৰ কোৱার্টাৰ ফাইনেলত অসমৰ আশ্মিতা

জন জন বিচাৰ
...✍ গুৱাহাটী



আন্তঃৰাষ্ট্রীয় বেডমিণ্টনৰ মঞ্চত অসমৰ বাবে গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিলে আশ্মিতা চলিহাই। বৃহস্পতিবাৰে ২২ অক্টোবৰ ফ্রেঞ্চ অ'পেন ২০২৬ বেডমিণ্টন প্রতিযোগিতাৰ দ্বিতীয় ৰাউণ্ডত ভাৰতীয় শ্বাটলাৰগৰাকীয়ে জাপানৰ বিশ্বৰ দ্বিতীয় স্থানপ্রাপ্ত আকানে য়ামাগুচিক পোনপটীয়া গেমত পৰাস্ত কৰি কোৱার্টাৰ ফাইনেলত প্রৱেশ কৰে। এই জয়ক আশ্মিতাৰ কেৰিয়াৰৰ অন্যতম বৃহৎ সফলতা হিচাপে বিবেচনা কৰা হৈছে।

২৭ বছৰীয়া আশ্মিতাই ৩৭ মিনিটৰ খেলত তিনিবাৰৰ বিশ্ব চেম্পিয়ন য়ামাগুচিক ২১-১৯, ২১-১৮ ব্যৱধানত পৰাস্ত কৰে। বিশ্ব বেডমিণ্টন ফেডাৰেচনৰ ছুপাৰ ৭৫০ শ্রেণীৰ এই প্রতিযোগিতাত বিশ্বৰ আগশাৰীৰ খেলুৰেৰ বিৰুদ্ধে আশ্মিতাৰ দৃঢ় প্রদর্শনে বিশেষ চর্চা লাভ কৰিছে।

বিশ্ব ৰেংকিঙত ৩৬সংখ্যক স্থানত থকা আশ্মিতাই প্রথম গেমত ১৮-১৪ ব্যৱধানত আগবাঢ়ি আছিল। কিন্তু য়ামাগুচিয়ে উভতি যুঁজ দি স্কৰ ১৮-১৮ কৰে। তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতাৰ মাজতো আশ্মিতাই চাপৰ সম্মুখীন হৈ স্থিৰতা বজাই ৰাখে আৰু ২১-১৯ ব্যৱধানত প্রথম গেমটো নিজৰ দখললৈ আনে।

দ্বিতীয় গেমত ৭-৭ সমতাৰ পিছত আশ্মিতাই ৰক্ষণাত্মক দক্ষতা, ক্ষিপ্র প্রত্যুত্তৰ আৰু নিখুঁত শ্বটৰ সহায়ত খেলৰ নিয়ন্ত্রণ নিজৰ হাতলৈ নিয়ে। আনহাতে, আশ্মিতাৰ চাপত য়ামাগুচিয়ে কেইবাটাও অনাহুত ভুল কৰে। অৱশেষত ২১-১৮ ব্যৱধানত দ্বিতীয় গেমটো জিকি অসমৰ খেলুৰেগৰাকীয়ে কোৱার্টাৰ ফাইনেলৰ টিকট নিশ্চিত কৰে।

উল্লেখ্য যে, যোৱা সপ্তাহত ডেনমার্ক অ'পেনত য়ামাগুচিৰ হাতত পোনপটীয়া গেমত পৰাস্ত হৈছিল আশ্মিতা। এইবাৰ ফ্রেঞ্চ অ'পেনত তাৰকা খেলুৰেগৰাকীক পৰাস্ত কৰি তেওঁ নিজৰ প্রদর্শনৰ উন্নতিৰো প্রমাণ দিলে।

চলিত বর্ষতে কোৰিয়া মাষ্টার্ছ ছুপাৰ ৩০০ প্রতিযোগিতাত নিজৰ প্রথমটো বি ডব্লিউ এফ ৱৰ্ল্ড ট্যুৰ খিতাপ জয় কৰা আশ্মিতাই এতিয়া কোৱার্টাৰ ফাইনেলত জাপানৰ অলিম্পিক পদক বিজয়ী তথা প্রাক্তন বিশ্ব চেম্পিয়ন নোজোমি ওকুহাৰা অথবা থাইলেণ্ডৰ বিশ্বৰ অষ্টম স্থানপ্রাপ্ত প'র্ণপাৱী চ'চুৰংৰ মুখামুখি হ'ব।

ইফালে, ভাৰতৰ তাৰকা শ্বাটলাৰ তথা দুবাৰৰ অলিম্পিক পদক বিজয়ী পি ভি সিন্ধুৱেও জাপানৰ ৰিকো গুদ্রিক ২১-১২, ২১-১৬ ব্যৱধানত পৰাস্ত কৰি কোৱার্টাৰ ফাইনেলত স্থান নিশ্চিত কৰিছে।

আশ্মিতাৰ এই জয়ে অসমৰ বেডমিণ্টন ক্ষেত্রতো নতুন আশাৰ সঞ্চাৰ কৰিছে। বিশ্বৰ দ্বিতীয় স্থানপ্রাপ্ত খেলুৰেক পৰাস্ত কৰি তেওঁ আন্তঃৰাষ্ট্রীয় পর্যায়ত নিজৰ সামর্থ্য প্রতিপন্ন কৰাৰ লগতে ৰাজ্যখনৰ উদীয়মান শ্বাটলাৰসকলৰ বাবেও অনুপ্রেৰণাৰ সৃষ্টি কৰিছে।

গোৱালপাৰাৰ কুঁৱাত আৱিষ্কাৰ দুবিধ নতুন ভূগর্ভস্থ মাছ

জন জন বিচাৰ
...✍ গুৱাহাটী



অসমৰ জীৱবৈচিত্র্যৰ ভাণ্ডাৰত সংযোজিত হ'ল নতুন অধ্যায়। গোৱালপাৰা জিলাৰ কুঁৱাত আৱিষ্কাৰ হৈছে বিজ্ঞানৰ বাবে পূর্বে অজ্ঞাত দুবিধ ভূগর্ভস্থ মাছ। ৰাজ্যৰ পৰিবেশ আৰু বনমন্ত্রী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই ২১ অক্টোবৰত এই আৱিষ্কাৰৰ কথা প্রকাশ কৰে। এই সন্ধানে অসমৰ কম অধ্যয়ন কৰা ভূগর্ভস্থ জলজ পৰিবেশতন্ত্রৰ জীৱবৈচিত্র্যৰ বিষয়ে নতুন তথ্য পোহৰলৈ আনিছে।

আৱিষ্কৃত মাছ দুবিধ হৈছে 'গিটচাক নাকানা' আৰু 'ৰাকথামিকথিছ আঞ্চি'। ইয়াৰে গিটচাক নাকানা এবিধ অতি ক্ষুদ্র, স্বচ্ছ দেহৰ আৰু চকুবিহীন মাছ। ইয়াৰ দৈর্ঘ্য প্রায় দুই চেণ্টিমিটাৰ। দেহ স্বচ্ছ হোৱাৰ বাবে মাছবিধৰ তেজ আৰু ভিতৰৰ অংগসমূহ বাহিৰৰ পৰাই দেখা যায়, যাৰ ফলত ইয়াৰ দেহ ৰঙচুৰা যেন লাগে।

আনহাতে, ৰাকথামিকথিছ আঞ্চি জলাশয়ত বাস কৰা ইল মাছৰ পৰিয়ালৰ অন্তর্গত। ইয়াৰ দেহ দীঘল আৰু সাপৰ দৰে। ভূগর্ভস্থ পানীৰ পৰিবেশত জীয়াই থকাৰ বাবে মাছবিধ বিশেষভাৱে অভিযোজিত।

মন্ত্রী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই সামাজিক মাধ্যমত প্রকাশ কৰা তথ্য অনুসৰি, গৱেষক ৰিমাৰিথি কে মাৰাকে প্রথম মাছবিধৰ নমুনা সংগ্রহ কৰিছিল আৰু ইয়াৰ এখন আলোকচিত্র নিজৰ তত্ত্বাৱধায়ক প্রেৰণ কৰিছিল। পৰৱর্তী সময়ত তেওঁৰ এগৰাকী আত্মীয়ই কুঁৱা পৰিষ্কাৰ কৰি থাকোঁতে আন এবিধ ভূগর্ভস্থ মাছৰ সন্ধান লাভ কৰে।

এই আৱিষ্কাৰসমূহৰ বৈজ্ঞানিক পৰীক্ষা-নিৰীক্ষাত আন্তঃৰাষ্ট্রীয় গৱেষকসকলেও সহযোগিতা আগবঢ়ায়। নমুনাসমূহৰ গঠন আৰু বৈশিষ্ট্য সূক্ষ্মভাৱে অধ্যয়ন কৰিবলৈ মাইক্রো-কম্পিউটেড টমগ্রাফী প্রযুক্তিৰ সহায় লোৱা হয়।

গৱেষকসকলে মাছ দুবিধ আৱিষ্কাৰ হোৱা নির্দিষ্ট স্থানৰ তথ্য প্রকাশ কৰা নাই। মন্ত্রীগৰাকীৰ মতে, ইয়াৰ উদ্দেশ্য হৈছে এই বিশেষ পৰিবেশতন্ত্রক সম্ভাব্য শোষণৰ পৰা সুৰক্ষিত ৰখা।

ভূগর্ভস্থ পানীৰ পৰিবেশতন্ত্র সাধাৰণতে মানুহৰ দৃষ্টিৰ আঁৰত থকাৰ বাবে ইয়াৰ জীৱবৈচিত্র্যৰ বিষয়ে এতিয়াও বহু কথা অজ্ঞাত হৈ আছে। বিশেষজ্ঞসকলৰ বাবে এই আৱিষ্কাৰ গুৰুত্বপূর্ণ, কিয়নো ই এনে পৰিবেশতন্ত্রত জীৱৰ অভিযোজন আৰু বিকাশৰ বিষয়ে অধিক গৱেষণাৰ পথ মুকলি কৰিব পাৰে।

মন্ত্রী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই ভূগর্ভস্থ বাসস্থান সংৰক্ষণৰ প্রয়োজনীয়তাৰ ওপৰতো গুৰুত্ব আৰোপ কৰে। তেওঁৰ মতে, উপৰিভাগৰ পানীত হোৱা প্রদূষণ ভূগর্ভস্থ পানীলৈ বিয়পি পৰিব পাৰে আৰু বিজ্ঞানৰ বাবেও এতিয়াও অজ্ঞাত বহু প্রজাতিৰ অস্তিত্ব বিপদাপন্ন কৰিব পাৰে।

এই সপ্তাহৰ ৰাশিফল

২৩ অক্টোবৰ ২০২৬ৰ পৰা ২৯ অক্টোবৰ ২০২৬ লৈ

মেষ : মানসিক সুখ শান্তি থাকিব। ব্যাৱসায় বাণিজ্যৰ ক্ষেত্রত শুভ। বিদ্যার্থীৰ বাৰে সপ্তাহটো শুভ।

বৃষ: অস্থিৰতা বৃদ্ধি হব পাৰে। দৰকাৰী সিদ্ধান্তগ্রহণৰ ক্ষেত্রত সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব। চেষ্টাৰ সাফল্য অর্জন।

মিথুন: কর্মক্ষেত্রত অস্থিৰতা বৃদ্ধি। দৰকাৰী সিদ্ধান্ত গ্রহণৰ ক্ষেত্রত সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব। ব্যয় বৃদ্ধিৰ সম্ভাৱনা আছে।

কর্কট: ধর্মীয় কার্য্যত মনোনিবেশ থাকিব। দৈনিক কর্ম ব্যস্ততা বৃদ্ধি হব পাৰে। সামাজিক কার্য্যৰ পৰা লাভ।

সিংহ: কর্মক্ষেত্রত সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব। পিতৃৰ শৰীৰ স্বাস্থ্যৰ প্রতি সচেতন হব। বাক্য বিনিময়ৰ ক্ষেত্রত সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব।

কন্যা : ব্যাৱসায় বাণিজ্যৰ ক্ষেত্রত শুভ ফল। আর্থীক ক্ষেত্রত শুভ। ধর্মীয় চেতনাৰ বৃদ্ধি।

তুলা: কর্মক্ষেত্রত সুনাম অর্জন। ব্যাৱসায় বাণিজ্যৰ ক্ষেত্রত শুভ। আকস্মিক অস্থিৰতা বৃদ্ধি হব পাৰে।

বৃশ্চিক: মানসিক সুখ শান্তি বৃদ্ধি। প্রতিযগিতামূলক কার্য্যত সফলতা। ব্যাৱসায় বাণিজ্যৰ ক্ষেত্রত শুভ।

ধনু : বিদ্যার্থীৰ সুখ্যাতি অর্জন। মানসিক উদ্বিগ্নতা বৃদ্ধি হব পাৰে। আকস্মিক কর্মব্যস্ততা বৃদ্ধি।

মকৰ: আদৰকাৰি বাদ বিবাদৰ পৰা আতৰি থাকক। কর্মক্ষেত্রত সপ্তাহটো শুভ। বিদ্যার্থীৰ শুভ।

কুম্ভ : আদার্কাৰী প্রতিযোগিতাৰ পৰা হানি। কঠোৰ বাক্য বানৰ ফলত মানসিক অশান্তি আহিব পাৰে। দৈনন্দিন কর্মব্যস্ততা বৃদ্ধি।

মীন: আনন্দ ফূর্তিৰ মাজেৰে সপ্তাহটো পাৰ হব। আর্থিক ক্ষেত্রত শুভ। আদাৰকাৰী কার্য্যত চেষ্টা পৰাক্রমৰ পৰা আতৰি থাকক।

- হিতেন শর্মা শাস্ত্রী
অধ্যাপক, বিশ্ব জ্যোতিষ বিদ্যাপীঠ, অসম শাখা
যোগাযোগ : ৯৮৫৪০২৬৭৭৯

অৱসৰৰ ১২ মাহ পূৰ্বেই পেঞ্চন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ

ফিনআছামৰ জৰিয়তে ৩,৯৭০ৰো অধিক কৰ্মচাৰীয়ে লাভ কৰিলে পিপিঅ'

জন জন বিচাৰ
...গুৱাহাটী

অসমত চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ পেঞ্চন প্ৰক্ৰিয়া অধিক সহজ, স্বচ্ছ আৰু ক্ষিপ্ৰ কৰি তোলাৰ লক্ষ্যৰে ৰাজ্য চৰকাৰে ফিনআছাম (FinAssam) ডিজিটেল মঞ্চৰ জৰিয়তে অৱসৰ-পূৰ্ব পেঞ্চন ব্যৱস্থা শক্তিশালী কৰিছে। মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ছ'চিয়েল মিডিয়া মঞ্চ 'এক্স'ত এই ব্যৱস্থাৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰি জনাইছে যে কৰ্মচাৰীৰ অৱসৰৰ ১২ মাহ পূৰ্বেই পেঞ্চন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰা হয়।

ৰাজ্য চৰকাৰৰ এই ব্যৱস্থাৰ মূল লক্ষ্য হৈছে অৱসৰৰ সময়ত কৰ্মচাৰীসকলে যাতে পেঞ্চন লাভৰ বাবে দীঘলীয়া প্ৰশাসনিক প্ৰক্ৰিয়া, অতিৰিক্ত কাগজ-পত্ৰ আৰু অনাৱশ্যক দৌৰা-দৌৰি কৰিবলগীয়া নহয়, সেয়া নিশ্চিত কৰা।

প্ৰকাশিত তথ্য অনুসৰি, ইতিমধ্যে ১১,০৪৭ৰো অধিক কৰ্মচাৰীক স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে এই ডিজিটেল ব্যৱস্থাৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে। আনহাতে, ৩,৯৭০ৰো অধিক কৰ্মচাৰীয়ে চাকৰিৰ অন্তিম দিনটোৰ পূৰ্বেই পেঞ্চন পেমেণ্ট অৰ্ডাৰ লাভ কৰিছে।

এই ব্যৱস্থাৰ অধীনত কৰ্মচাৰীসকলে পেঞ্চনৰ বাবে হাতেৰে লিখা আবেদন দাখিল কৰা অথবা সেৱাৰ মূল নথি-পত্ৰ গুৱাহাটীলৈ কঢ়িয়াই নিয়াৰ প্ৰয়োজন নহয়। জিলাভিত্তিক স্থায়ী সমিতিসমূহে স্থানীয় পৰ্যায়তে কৰ্মচাৰীসকলৰ সেৱাৰ তথ্য আৰু দৰমহা নিৰ্ধাৰণৰ নথি পৰীক্ষা কৰে। তাৰ পিছত ডিজিটেল সেৱা-প্ৰমাণপত্ৰ জাৰি কৰা হয়।

ফিনআছামে অৱসৰৰ ১২ মাহ পূৰ্বেই কৰ্মচাৰীসকলৰ অৱসৰ-সম্পৰ্কীয় তথ্য স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে প্ৰস্তুত কৰে। পেঞ্চনৰ প্ৰস্তাৱসমূহৰ প্ৰমাণীকৰণৰ বাবে NICDSign 3.0 ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে। লগতে সুৰক্ষিত কিউআৰ ক'ড আৰু ডিজিলকাৰৰ জৰিয়তে প্ৰয়োজনীয় নথি-পত্ৰ উপলব্ধ কৰাৰ ব্যৱস্থাও কৰা হৈছে।

২০২৬-২৭ বৰ্ষত অৱসৰ লবলগীয়া কৰ্মচাৰীসকলৰ ক্ষেত্ৰতো এই ব্যৱস্থাই পেঞ্চন প্ৰক্ৰিয়া অধিক সময়োপযোগী আৰু কাগজবিহীন কৰি তোলাৰ লক্ষ্য লৈছে। অৱসৰৰ পূৰ্বেই প্ৰয়োজনীয় প্ৰশাসনিক কাম সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰিলে কৰ্মচাৰীসকলে অৱসৰৰ পিছত সময়মতে পেঞ্চন লাভ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সকাহ পাব বুলি আশা কৰা হৈছে।

অমিত শাহক জন্মদিনৰ শুভেচ্ছা হিমন্তৰ, ২০২৯১ ভিতৰত ড্ৰাগছৰ নেটৱৰ্ক উৎখাতৰ সংকল্প

গুৱাহাটী : কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহৰ জন্মদিন উপলক্ষে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰাৰ লগতে দেশৰ আভ্যন্তৰীণ নিৰাপত্তা শক্তিশালী কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁৰ নেতৃত্বৰ প্ৰশংসা কৰে। একে সময়তে ২০২৯ চনৰ ভিতৰত ড্ৰাগছৰ অবৈধ ব্যৱসায় আৰু সৰবৰাহৰ নেটৱৰ্ক উৎখাত কৰাৰ কেন্দ্ৰীয় লক্ষ্যত অসম চৰকাৰে সম্পূৰ্ণ সহযোগিতা আগবঢ়াব বুলি তেওঁ পুনৰ স্পষ্ট কৰে। সামাজিক মাধ্যম 'এক্স'ত দিয়া এটা বাৰ্তাত মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই অসমৰ জনসাধাৰণৰ হৈ অমিত শাহক জন্মদিনৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জনায়। তেওঁ কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীৰ সুস্বাস্থ্য আৰু দীৰ্ঘায়ু কামনা কৰে।



মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অমিত শাহক ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাৰ্থৰ প্ৰতি দায়বদ্ধ এগৰাকী নেতা হিচাপে অভিহিত কৰে। তেওঁৰ মতে, শাহৰ নেতৃত্বত দেশৰ আভ্যন্তৰীণ নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা অধিক শক্তিশালী হৈছে আৰু নক্সালবাদ নিৰ্মূলৰ ক্ষেত্ৰতো উল্লেখযোগ্য অগ্ৰগতি লাভ কৰা হৈছে।

অসমৰ প্ৰতি কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীৰ বিশেষ গুৰুত্বৰ কথাও মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উল্লেখ কৰে। ৰাজ্যত অপৰাধ হ্ৰাস কৰা আৰু এখন 'বিকশিত অসম' গঢ়ি তোলাৰ প্ৰচেষ্টাত শাহে সহযোগিতা আগবঢ়াই অহা বুলি তেওঁ কয়।

ইফালে, দেশৰ পৰা ড্ৰাগছৰ অবৈধ ব্যৱসায় আৰু সৰবৰাহৰ নেটৱৰ্ক উৎখাত কৰাৰ লক্ষ্যত অসমে সম্পূৰ্ণ সহযোগিতা আগবঢ়াব বুলি শৰ্মাই উল্লেখ কৰে। ২০২৯ চনৰ ভিতৰত এই লক্ষ্য বাস্তৱায়িত কৰাৰ বাবে কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্যৰ মাজত সমন্বিত প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰখাৰ ওপৰতো গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছে।

ঘোঁৰাত আগমন, নৌকাৰে গমন দেৱী দুৰ্গাৰ

জন জন বিচাৰ
...নয়নমণি ফুকন, নাজিৰা

শৰতৰ সন্ধিয়া ঘোঁৰাত আগমন, বিজয়া দশমীত নৌকাৰে গমন-পৰম্পৰাগত বিশ্বাস আৰু ভক্তিৰ আবেগৰ মাজেৰে নাজিৰাত সামৰণি পৰে শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱৰ। বানে ধোৱা নাজিৰা সমজিলাত আনন্দ-উল্লাসৰ মাজেৰে শান্তিপূৰ্ণভাৱে সম্পন্ন হোৱা দুৰ্গাপূজাৰ অন্তিম দিনটোত বশিষ্ঠ গংগা নামেৰে খ্যাত দিখৌ নদীৰ জলধাৰাত অশ্ৰুসিক্ত নয়নেৰে বিদায় জনোৱা হয় মহিষমৰ্দিনী দেৱী দুৰ্গাক।

নাজিৰা নগৰৰ পূজা ডুবি ঘাটকে ধৰি বিভিন্ন বিসৰ্জনস্থলীত দেৱীৰ প্ৰতিমা লৈ ভক্তসকলে শোভাযাত্ৰা কৰে। প্ৰথম অসম আৰক্ষী বাহিনী, শতিকা প্ৰাচীন নাজিৰা পূজা মন্দিৰ, অ' এন জি চি অসম সম্পদৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ আৱাসিক অঞ্চল, নৰসিংহ দুৰ্গাপূজা, মিলন মন্দিৰ, লিগিৰীপুখুৰী চাহ বাগিচা, ষ্টেচন তিনিআলি, কলেজ তিনিআলি, মাদুৰী, মেকিপুৰ, বামুণপুখুৰী আৰু লক্ষ্মীজান চাহ বাগিচাৰ লগতে ২৫ নং (অ' এন জি চি) অসম আৰক্ষী বেটেলিয়ন আৰু গেলেকী চাৰিআলি দুৰ্গাপূজাৰ প্ৰতিমাসমূহো দিখৌৰ জলধাৰাত



বিসৰ্জন দিয়া হয়। বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা প্ৰায় অৰ্ধশতাধিক প্ৰতিমাৰ বিসৰ্জনেৰে সামৰণি পৰে এইবাৰৰ দুৰ্গোৎসৱ।

নাজিৰা সমজিলাৰ অন্তৰ্গত বিভিন্ন আৰক্ষী থানা এলেকাতো ব্যাপক আয়োজন কৰা হৈছিল দুৰ্গাপূজাৰ। নাজিৰা আদৰ্শ আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত ১৩খন, গেলেকী আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত ৬খন, শিমলুগুৰি আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত ১০খন, বিহুৰ আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত ৫খন, হালোৱাটিং আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত ৮খন, নামতি আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত ২খন, আমগুৰি আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত ১২খন আৰু মথুৰাপুৰ আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত ৫খন পূজাস্থলীত দুৰ্গোৎসৱ অনুষ্ঠিত হয়।

অৱশ্যে, পূৰ্ববৰ্ষসমূহৰ তুলনাত এইবাৰ পূজাস্থলীসমূহত ভক্ত আৰু দৰ্শনাৰ্থীৰ সমাগম কিছুহ্ৰাস পোৱা পৰিলক্ষিত হয়। উৎসৱক কেন্দ্ৰ কৰি অস্থায়ীভাৱে সৰু-সুৰা ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰা ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীসকলেও আশানুৰূপ লাভ অৰ্জন কৰিব নোৱাৰিলে বুলি মত প্ৰকাশ কৰে।

উল্লেখ্য যে, ষষ্ঠীৰ দিনা বেদীত প্ৰতিষ্ঠা কৰা দেৱী দুৰ্গাক বিজয়া দশমীৰ দিনা বিদায় জনোৱাৰ পৰম্পৰাই ভক্তসকলৰ মনত আনন্দৰ মাজতো বিৰহৰ অনুভূতি কঢ়িয়াই আনে। দিখৌৰ বুকুত প্ৰতিমা বিসৰ্জনৰ সময়ত ভক্তসকলৰ প্ৰাৰ্থনা আৰু অশ্ৰুসিক্ত বিদায়ৰ মাজেৰে নাজিৰাত এইবাৰৰ শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱৰ সামৰণি পৰে।

দুৰ্গাপূজাত গুৱাহাটীত পথ দুৰ্ঘটনাত ৯জনৰ মৃত্যু

গুৱাহাটী: দুৰ্গাপূজাৰ আনন্দ-উৎসৱৰ মাজতে গুৱাহাটীত পথ দুৰ্ঘটনাই উদ্বেগজনক পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰে। ১৬ৰ পৰা ২১ অক্টোবৰলৈ ছয় দিনত মহানগৰীত সংঘটিত পথ দুৰ্ঘটনাত ৯জন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ বিপৰীতে ১০৫জন আহত হয়। গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতাল (জিএমচিএইচ)ৰ তথ্য অনুসৰি, উক্ত সময়ছোৱাত পথ দুৰ্ঘটনাত আহত মুঠ ১১৪জন লোকক হাস্পতালখনত চিকিৎসা প্ৰদান কৰা হৈছিল। ইয়াৰে ৯জনৰ আঘাতৰ ফলত মৃত্যু হয়।

দুৰ্গাপূজাৰ সময়ত পূজাৰ মণ্ডপ দৰ্শন, উৎসৱত অংশগ্ৰহণ আৰু এঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ অহা-যোৱা কৰা লোকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱাৰ ফলত মহানগৰীৰ পথসমূহত যান-বাহনৰ চলাচল বৃদ্ধি পায়। এনে পৰিস্থিতিত সংঘটিত দুৰ্ঘটনাসমূহে উৎসৱৰ বতৰত পথ সুৰক্ষাৰ প্ৰত্যাহ্বান পুনৰ উন্মোচন কৰিছে।

জিএমচিএইচৰ তথ্য অনুসৰি, দুৰ্ঘটনাত আহতসকলৰ ভিতৰত ৬৭জন পুৰুষ আৰু ১৫গৰাকী মহিলা আছিল। আহতসকলৰ প্ৰায় ২০ শতাংশৰ অৱস্থা সংকটজনক আছিল আৰু তেওঁলোকৰ চিকিৎসা অব্যাহত ৰাখিবলগীয়া হৈছিল।

সম্পাদকীয়

ঔষধৰ দামত ৩০ শতাংশৰ সীমা, কিন্তু চিকিৎসাৰ ব্যয় নিয়ন্ত্রণ কৰিব কোনে?

কেন্সাৰৰ দৰে মাৰাত্মক ৰোগৰ চিকিৎসা কেৱল জীৱন-মৃত্যুৰ যুঁজেই নহয়, বহু পৰিয়ালৰ বাবে ই আৰ্থিক সর্বনাশৰো কাৰণ। চিকিৎসাৰ ব্যয় বহন কৰিবলৈ গৈ পৰিয়ালে ঋণৰ বোজাত ডুবিবলগীয়া হোৱা এখন দেশত ঔষধৰ মূল্য নিয়ন্ত্রণ কৰাটো চৰকাৰৰ দয়া নহয়, ই জনস্বাস্থ্যৰ প্রতি মৌলিক দায়িত্ব। এই পৰিপ্রেক্ষিতত কেন্সাৰ প্রতিৰোধী গুৰুত্বপূর্ণ ঔষধৰ ব্যৱসায়িক লাভৰ হাৰত ৩০ শতাংশৰ সীমা নির্ধাৰণৰ পদক্ষেপ আদৰণীয়। কিন্তু প্রশ্নটো হ'ল-ইয়াৰ দ্বাৰাই সাধাৰণ ৰোগীৰ চিকিৎসাৰ ব্যয় সঁচাকৈ কমিবনে?

উচ্চতম ন্যায়ালয়ত উত্থাপিত বিষয়সমূহে স্বাস্থ্যখণ্ডৰ এক উদ্বেগজনক ছবি দাঙি ধৰিছে। পাঁচ হাজাৰ টকাত ক্রয় কৰা কার্ডিয়াক ষ্টেণ্টৰ সর্বোচ্চ খুচুৰা মূল্য ২৫ হাজাৰ টকা হোৱা, অথবা চিকিৎসাত ব্যৱহৃত সামগ্রীৰ ক্রয়মূল্যতকৈ বহু গুণ অধিক দাম ৰোগীৰ পৰা আদায় কৰাৰ অভিযোগে ব্যৱস্থাটোৰ স্বচ্ছতাক লৈ প্রশ্ন তোলে। কর্ণাটক আৰু উত্তৰ প্রদেশত কিছুমান সামগ্রীৰ মূল্য ক্রয়মূল্যৰ তুলনাত ক্রমে ৫২ আৰু ৬৭ গুণলৈ অধিক হোৱা তথ্যও উদ্বেগজনক।

সমস্যাটো কেৱল ঔষধৰ লাভৰ হাৰত সীমাবদ্ধ নহয়। চিকিৎসালয়ত ভর্তি হোৱাৰ পিছত ৰোগীয়ে প্রায়ে চিকিৎসালয়ৰ নিজা ফার্মাচীৰ পৰাই ঔষধ আৰু চিকিৎসা-সামগ্রী কিনিবলৈ বাধ্য হয়। ইয়াৰ উপৰি কোঠাৰ ভাড়া, পৰীক্ষা-নিৰীক্ষাৰ মাচুল আৰু চিকিৎসাৰ সামগ্রিক ব্যয়ৰ ওপৰতো নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন।

চিকিৎসালয়ৰ মাচুল স্বচ্ছ কৰা, মূল্যতালিকা প্রকাশ বাধ্যতামূলক কৰা আৰু নিয়ম উলংঘাকাৰীৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্রহণ কৰাটো জৰুৰী। চৰকাৰী নিয়ম কাগজতে সীমাবদ্ধ থাকিলে ৰোগীয়ে সকাহ নাপায়।

স্বাস্থ্যসেৱা কেৱল লাভ অর্জনৰ ব্যৱসায় হ'ব নোৱাৰে। ঔষধৰ মূল্যত ৩০ শতাংশৰ সীমা এক আৰম্ভণি; এতিয়া প্রয়োজন সমগ্র চিকিৎসা ব্যৱস্থাৰ জবাবদিহিতা নিশ্চিত কৰা। কাৰণ, ৰোগীৰ জীৱন ৰক্ষা কৰাই চিকিৎসাৰ উদ্দেশ্য-তেওঁৰ সঞ্চয় নিঃশেষ কৰা নহয়।

ফ্রেন্স ফ্রাই, ভাৰতত নহয় ভাই

জন জন বিচাৰ

...✍ সুধীশ পাচৌৰি

ফ্রান্স জ্বলিছে। দেশখনৰ শত্রুসকলে যেন তাক 'ফ্রেন্স ফ্রাই'ৰ দৰে ভাজি পেলাইছে। ইটালী, স্পেইন, গ্রীচ, পর্তুগাল, বেলজিয়াম, টিউনিছিয়া, আলবেনিয়া আৰু আর্জেণ্টিনাকে ধৰি আন কেইবাখনো দেশতো একেধৰণৰ আন্দোলনে জোকাৰি গৈছে। ৰুছোৱ 'আধুনিক সমাজ'ৰ ধাৰণাক সম্ভৱ কৰি তোলা 'সামাজিক চুক্তি' আৰু বিশ্বক গণতন্ত্রৰ পথ দেখুওৱা ফৰাচী বিপ্লৱৰ তিনিটা আদর্শ-'সমতা, ভ্রাতৃত্ব আৰু স্বাধীনতা' আজি যেন ধূলিসাৎ হৈছে।

ফ্রান্সৰ ১২৫ বছৰ পুৰণি এখন পৌৰসভাৰ ভৱন জ্বলাই দিয়া হৈছে। 'জোন অৰ আর্ক'ৰ মূর্তিত হিজাব পিন্ধোৱা হৈছে। বিশ্বৰ বিৰল আৰু অত্যন্ত দামী ফেশ্বন ব্রেণ্ডৰ বিপণীসমূহত সজাই থোৱা সামগ্রী লুট কৰি সেইবোৰত জুই লগোৱা হৈছে। 'বার্কিন' তেনে এটা বিলাসী বেগৰ ব্রেণ্ড, যিটো সকলোৱে কিনিব নোৱাৰে। প্রায় পাঁচ লাখ ডলাৰ (৪.১ কোটি টকা) মূল্যৰ এই বিশেষ বেগটো পৰম্পৰাগতভাৱে বিশ্বৰ অতি ধনী আৰু প্রভাৱশালী লোকসকলৰ বাবেহে উপলব্ধ। ইয়াৰ আগতীয়া বুকিঙৰ ক্ষেত্রতো গ্রাহকৰ পাৰিবাৰিক অভিজাত পৰিচয় পৰীক্ষা কৰা হয় বুলি কোৱা হয়। বছৰ বছৰ ধৰি ইয়াৰ যোগানৰ বাবে অপেক্ষা কৰিবলগীয়া হয়। বিশ্বৰ অতি ধনী মহিলাসকলৰ একাংশক এই বেগ লৈ গৌৰৰ কৰা দেখা যায়।

এনে নামী ব্রেণ্ডৰ বিপণীৰ উপৰি 'লুই ভিটন', 'চেনেল', 'ক্রিষ্টিয়ান ডিঅ'ৰ', 'ৰ'লেক্স', 'ছ'ন'ৰন' আৰু 'এপল ষ্ট'ৰ'ৰ দৰে বিলাসী পুঁজিবাদৰ প্রতীকস্বৰূপ বিপণীসমূহতো লুটপাত চলোৱা হৈছে। তথাপি ফ্রান্সৰ সংবাদ মাধ্যম আৰু শাসনাধিষ্ঠিত মহলৰ একাংশই এই তিক্ত বাস্তৱক উপেক্ষা কৰি কৈ আহিছে যে ছাত্র-ছাত্রীৰ আন্দোলনটো শান্তিপূর্ণ আছিল, আন্দোলনকাৰীসকলে একো কৰা নাছিল আৰু যি ঘটিছে, তাৰ বাবে প্রশাসন তথা আৰক্ষীয়েই দায়ী।

এই কথা সঁচা যে ফ্রান্সৰ বিলাসী পুঁজিবাদৰ বিশ্বজনীন প্রতীকসমূহে ধনী-দুখীয়াৰ মাজৰ ব্যৱধান বৃদ্ধি কৰাত ভূমিকা লৈছে। বহু লুটপাতকাৰীয়ে এই ব্রেণ্ডসমূহ লুট কৰি আৰু ধ্বংস কৰি সেই ব্যৱস্থাৰ বিৰুদ্ধে প্রতিশোধ লোৱা বুলি ভাবিছে। কিন্তু এনে লুটপাতৰ পিছতো এই ব্রেণ্ডসমূহৰ প্রতি মানুহৰ আকর্ষণ কমাৰ পৰিৱর্তে কেতিয়াবা আৰু বাঢ়ে, চাহিদাও বৃদ্ধি পায়। ফলত বিলাসী পুঁজিবাদৰ ব্যৱস্থাটো অধিক শক্তিশালী হৈ উঠে। কিছুমানৰ বাবে এই বিলাসী ব্রেণ্ডসমূহ যেন চয়তানৰ প্রতীক।

কেইবছৰমান পূর্বে আমেৰিকাৰ বিশ্ব বাণিজ্য কেন্দ্রৰ ধ্বংসপ্রাপ্ত দুটা অট্টালিকাকো চয়তানৰ প্রতীক বুলি গণ্য কৰি উৰুৱাই দিয়া হৈছিল। ইয়াৰ অর্থ হ'ল, ফ্রান্সক জুই আৰু লুটপাতৰ মাজলৈ ঠেলি দিয়া আন্দোলনটো কেৱল শান্তিপূর্ণ ছাত্র আন্দোলন নহয়; ইয়াৰ মাজত এক প্রকাৰৰ 'শ্রেণীযুদ্ধ'ৰ চৰিত্রও আছে।

এই জুই আৰু হিংসাৰ লক্ষ্য হৈ পৰিছে এনে কিছুমান নাগৰিকো, যিসকলে আন্দোলনৰ পূর্বে শৰণার্থীসকলৰ পক্ষত মাত মাতিছিল আৰু তেওঁলোকক সহায় কৰিছিল। এনে এগৰাকী মহিলাই তেওঁৰ দোকানখন লুটপাত আৰু আক্রমণৰ সম্মুখীন হোৱাৰ পিছত জনাইছিল যে তেওঁ শৰণার্থীসকলক বিভিন্ন ধৰণে সহায় কৰি আহিছিল। কিন্তু যেতিয়া লুটপাতকাৰীয়ে তেওঁৰ দোকানত লুটপাত আৰম্ভ কৰিলে, তেতিয়া তেওঁৰ কোনো অনুৰোধেই তেওঁলোকৰ কাণত নপৰিল।

এজন ফৰাচী নাগৰিকৰ অভিজ্ঞতাও একেই। তেওঁ শৰণার্থীসকলক আদৰণি জনাই অনুষ্ঠিত হোৱা সমদলত সদায় পোষ্টাৰ লৈ থিয় দিছিল। কিন্তু তেওঁৰ দোকানত লুটপাত চলোৱাৰ সময়ত লুটপাতকাৰীসকলে তেওঁৰ কোনো কথাই নুশুনিলে। এইদৰে তেওঁ যেন নিজৰ মানৱীয় সহানুভূতিৰ বাবেই শাস্তি পালে।

পশ্চিমীয়া সংবাদ মাধ্যমৰ মতে, বিলাসী পুঁজিবাদৰ বিশ্বজনীন ৰাজধানী পেৰিছকে ধৰি ফ্রান্সৰ বিভিন্ন চহৰক জুইৰ মাজলৈ ঠেলি দিয়া এই হিংসাত্মক আন্দোলনৰ আৰম্ভণি হৈছিল জৰাজীর্ণ বিদ্যালয় ব্যৱস্থাৰ বিৰুদ্ধে জমা হোৱা ক্ষোভৰ পৰা। পিছলৈ চৰকাৰী ব্যয় হ্রাসৰ নীতি আৰু অৱসৰৰ বয়স বৃদ্ধিৰ সিদ্ধান্তক লৈও ক্ষোভ বাঢ়িছিল।

ফ্রান্সৰ এই লুটপাত আৰু অগ্নিসংযোগৰ দৃশ্য দেখি ভাৰতৰো একাংশ বিৰোধী ৰাজনৈতিক উপাদানক উৎফুল্লিত হোৱা যেন দেখা গৈছে। দেশৰ এগৰাকী 'থলুৱা লেনিনে' ইতিমধ্যে 'শাসন পৰিৱর্তন'ৰ আহ্বান জনাইছে আৰু এই প্রক্রিয়াত ৰক্তপাত হ'ব পাৰে বুলিও কৈছে। আন এগৰাকী 'থলুৱা ৰোজা লুক্সেমবার্গে' বাংলাদেশৰ দৰে ভাৰততো শাসন পৰিৱর্তনৰ দাবী জনোৱা যেন দেখা গৈছে।

কিছুসময়ৰ পিছতে কিছুমান উগ্রপন্থী উপাদানে আন্দোলনটোক নিজৰ নিয়ন্ত্রণলৈ লৈ যায়। সেইবাবেই লুটপাত আৰু অগ্নিসংযোগৰ ঘটনাসমূহ নির্বাচিত লক্ষ্যত কেন্দ্রীভূত হোৱা বুলি কোৱা হৈছে। কিন্তু ইউৰোপীয় সংবাদ মাধ্যমে এই ঘটনাৰ আঁৱত কাম কৰা বুলি অভিযোগ উত্থাপিত 'ডীপ ষ্টেট'ৰ ভূমিকাক লৈ বিশেষ আলোচনা কৰা নাই।

আনহাতে, পশ্চিমীয়া দেশৰ বহু ভাষ্যকাৰে এতিয়াও এই 'জেন-জি আন্দোলন'ক ১৯৬৮ চনৰ ছাত্র আন্দোলনৰ পুনৰাবৃত্তি বুলিয়েই অভিহিত কৰিছে। কিন্তু জেন-জিৰ ভাষাত ক'বলৈ গ'লে, ইউৰোপৰ কেইবাখনো দেশত চলি থকা এই আন্দোলনৰ আঁৱত আছে বিশ্বৰ 'ভূকা মানসিকতা'-অর্থাৎ অস্থিৰ, অনিশ্চিত, জটিল আৰু অস্পষ্ট পৰিস্থিতিৰ মাজত গঢ় লৈ উঠা এক মানসিকতা। এই পৰিস্থিতিৰ সৈতে অৰাজকতাবাদী কার্যসূচীৰো সম্পর্ক আছে।

ফ্রান্সৰ অগ্নিগর্ভ পৰিস্থিতি দেখি 'ভূকা মানসিকতা'ৰ অন্যতম প্রবক্তা বুলি কটাক্ষ কৰা ড'নাল্ড ট্রাম্পেও কৈছে যে শৰণার্থীসকলে ফ্রান্সক দখল কৰি লৈছে আৰু দেশখনে নিজৰ সীমান্ত বন্ধ কৰি দিব লাগে।

ফ্রান্সৰ এই লুটপাত আৰু অগ্নিসংযোগৰ দৃশ্য দেখি ভাৰতৰো একাংশ বিৰোধী ৰাজনৈতিক উপাদানক উৎফুল্লিত হোৱা যেন দেখা গৈছে। দেশৰ এগৰাকী 'থলুৱা লেনিনে' ইতিমধ্যে 'শাসন পৰিৱর্তন'ৰ আহ্বান জনাইছে আৰু এই প্রক্রিয়াত ৰক্তপাত হ'ব পাৰে বুলিও কৈছে। আন এগৰাকী 'থলুৱা ৰোজা লুক্সেমবার্গে' বাংলাদেশৰ দৰে ভাৰততো শাসন পৰিৱর্তনৰ দাবী জনোৱা যেন দেখা গৈছে।

বিৰোধী শিবিৰৰ এগৰাকী নেতাই নিজৰ সৈতে শাসক পক্ষৰ 'মিতিৰালি' থকাৰ অভিযোগৰ প্রতিশোধ হিচাপে আন্দোলনকাৰীয়ে আলবেনিয়াৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ভৱন জ্বলাই দিয়াৰ ঘটনাকো ন্যায্যতা প্রদান কৰা যেন দেখা গৈছে। একেদৰে, বিৰোধী শিবিৰৰ আন এগৰাকী নেতাই দেশৰ মুখ্য ন্যায়াধীশৰ নাম উল্লেখ কৰি কৈছে-যদি আপোনাৰ দ্বাৰা আইন-শৃংখলা পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ কৰা সম্ভৱ নহয়, তেন্তে পদত্যাগ কৰক; আমি নতুন মুখ্য ন্যায়াধীশ বাছি ল'ম।

আৰু বিৰোধী শিবিৰৰ এগৰাকী 'থলুৱা মাক্স ছাৰে' ইতিমধ্যে কৈছে যে গণতন্ত্র সংসদৰ পৰা নহয়, ৰাজপথৰ পৰাহে চলিব লাগে।

সামাজিক মাধ্যমত সক্রিয় বহু 'বিপ্লৱী জ্ঞানী'য়ে প্রতিদিনে, প্রতিটো মুহূর্তে শাসন পৰিৱর্তনৰ দাবী জনাই থাকে। তেওঁলোকৰ বহুতেই আনকি ক'বলৈ ধৰিছে-ফ্রান্সত যি ঘটিছে, ভাৰততো তেনে হ'ব লাগে। অর্থাৎ, 'আমি নিজেও ডুবিম, প্রিয়তম, তোমাকো ডুবাম' এনে পৰিস্থিতিত এটা টেলিভিছন চেনেলৰ সঞ্চালকে প্রশ্ন কৰিছে-ছাৰজী আপোনালোকে যদি এনে কৰে, তেন্তে ফ্রান্সৰ দেশপ্রেমী নাগৰিকসকলৰ দৰে ভাৰতৰ দেশপ্রেমী নাগৰিকসকলো হাত সাৰটি বহি থাকিবনে? গতিকে আমাৰ বক্তব্য এটাই-'ফ্রেন্স ফ্রাই, ভাৰতত নহয় ভাই'।

মুছলমান দেশসমূহৰ নতুন প্ৰতিৰক্ষা মিত্ৰতা

জন জন বিচাৰ
...✍ দোহা

পাকিস্তান-তুৰস্ক-কাটাৰ-ইণ্ডোনেছিয়াৰ 'বদৰ চুক্তি', অস্ত্ৰ নিৰ্মাণত যৌথ উদ্যোগ

অস্ত্ৰ নিৰ্মাণ, সামৰিক প্ৰযুক্তিৰ আদান-প্ৰদান আৰু প্ৰতিৰক্ষা গৱেষণাত সহযোগিতা বৃদ্ধিৰ লক্ষ্যৰে পাকিস্তান, তুৰস্ক, কাটাৰ আৰু ইণ্ডোনেছিয়াই নতুন প্ৰতিৰক্ষা চুক্তিত স্বাক্ষৰ কৰিছে। বুধবাৰে কাটাৰৰ ৰাজধানী দোহাত স্বাক্ষৰিত এই 'বদৰ চুক্তি'ৰ জৰিয়তে চাৰিওখন দেশে নিজৰ প্ৰতিৰক্ষা উদ্যোগৰ সামৰ্থ্য একত্ৰিত কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে। এই পদক্ষেপে মুছলমান-প্ৰধান দেশসমূহৰ মাজত ক্ৰমবৰ্ধমান সামৰিক সহযোগিতাক নতুন মাত্ৰা দিয়াৰ লগতে আঞ্চলিক প্ৰতিৰক্ষা সমীকৰণতো প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে।

চুক্তিখনৰ অধীনত দেশকেইখনে অস্ত্ৰ উৎপাদন, সামৰিক প্ৰযুক্তি, দক্ষ কৰ্মশক্তি, বিনিয়োগ, প্ৰশিক্ষণ আৰু গৱেষণাৰ ক্ষেত্ৰত পৰস্পৰক সহযোগিতা আগবঢ়াব। ইয়াৰ মূল উদ্দেশ্য হৈছে বিদেশী অস্ত্ৰ যোগানকাৰীৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীলতা কমোৱা, নিজা উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰা আৰু প্ৰতিৰক্ষা উদ্যোগক অধিক শক্তিশালী কৰা।

এই অংশীদাৰিত্বত তুৰস্কৰ আধুনিক সামৰিক প্ৰযুক্তি আৰু অস্ত্ৰ নিৰ্মাণৰ অভিজ্ঞতা, পাকিস্তান আৰু ইণ্ডোনেছিয়াৰ উৎপাদন সামৰ্থ্য তথা বৃহৎ বজাৰ, আৰু কাটাৰৰ বিনিয়োগৰ ক্ষমতাই গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিব পাৰে। বিশেষজ্ঞসকলৰ মতে, ইয়াৰ ফলত অস্ত্ৰ উৎপাদনৰ ব্যয় হ্ৰাস, নতুন কৰ্মসংস্থাপনৰ সৃষ্টি আৰু সদস্য দেশসমূহৰ প্ৰতিৰক্ষা উদ্যোগৰ সম্প্ৰসাৰণৰ সুযোগ বৃদ্ধি পাব পাৰে।

পাকিস্তান আৰু তুৰস্কৰ মাজত যুদ্ধজাহাজ নিৰ্মাণৰ প্ৰকল্প ইতিমধ্যে চলি আছে। ইণ্ডোনেছিয়া আৰু তুৰস্কইও যৌথভাৱে টেংক নিৰ্মাণৰ কাম কৰি আহিছে। নতুন চুক্তিয়ে এনে পৃথক প্ৰকল্পসমূহক অধিক সুসংগঠিত সহযোগিতাৰ কাঠামোৰ অধীনলৈ অনাৰ পথ মুকলি কৰিব পাৰে।

ইয়াৰ পূৰ্বে ছৌদি আৰব, পাকিস্তান আৰু তুৰস্কৰ মাজত সামৰিক সহযোগিতাৰ উদ্যোগে চৰ্চা লাভ কৰিছিল। অৱশ্যে 'মহুৱা চুক্তি' আৰু 'বদৰ চুক্তি'ৰ উদ্দেশ্য একে নহয়-প্ৰথমটোৱে সামূহিক নিৰাপত্তা আৰু সামৰিক সহযোগিতাত গুৰুত্ব দিয়ে, আনহাতে দ্বিতীয়টোৱ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈছে অস্ত্ৰ উৎপাদন আৰু প্ৰতিৰক্ষা উদ্যোগৰ বিকাশ। এই নতুন সহযোগিতাই আমেৰিকাকে ধৰি পৰম্পৰাগত অস্ত্ৰ যোগানকাৰী দেশসমূহৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীলতা কমোৱাৰ প্ৰচেষ্টাক প্ৰতিফলিত কৰে। অৱশ্যে চুক্তিখনে প্ৰকৃততে কিমান উৎপাদন, প্ৰযুক্তিগত আত্মনিৰ্ভৰশীলতা আৰু সামৰিক সক্ষমতা সৃষ্টি কৰিব, সেয়া নিৰ্ভৰ কৰিব ইয়াৰ বাস্তৰায়ন, বিনিয়োগ আৰু দেশসমূহৰ মাজৰ দীৰ্ঘম্যাদী সমন্বয়ৰ ওপৰত।

ৰাছিয়াৰ ক্ষেপণাস্ত্ৰ আক্ৰমণৰ আগজাননী ৩ দিন বন্ধ, আমেৰিকাৰ ভূমিকাক লৈ জেলেনস্কিৰ উদ্বেগ

জন জন বিচাৰ
...✍ ৱাশ্বিংটন

ৰাছিয়াৰ বেলিষ্টিক ক্ষেপণাস্ত্ৰ আক্ৰমণৰ আগতীয়া সতৰ্কবাণী যোগান ধৰা গুৰুত্বপূৰ্ণ চোৱাংচোৱা তথ্য আমেৰিকাই তিনিদিনৰ বাবে ইউক্ৰেইনৰ সৈতে ভাগ-বতৰা কৰা বন্ধ কৰি দিছিল বুলি অভিযোগ কৰিছে ৰাষ্ট্ৰপতি ভলোডিমিৰ জেলেনস্কিয়ে। অৱশ্যে, আমেৰিকাই পুনৰ এই তথ্য যোগান আৰম্ভ কৰিছে বুলি তেওঁ জানিবলৈ দিছে। একে সময়তে, ইউক্ৰেইনৰ সামৰিক বাহিনীয়ে ব্যৱহাৰ কৰা ষ্টাৰলিংক উপগ্ৰহ-যোগাযোগ সেৱাত আৰোপ কৰা কিছুমান বাধা এতিয়াও সম্পূৰ্ণৰূপে প্ৰত্যাহাৰ কৰা হোৱা নাই বুলিও তেওঁ অভিযোগ কৰিছে।

এনবিচিৰ 'মিট দ্য প্ৰেছ' অনুষ্ঠানত দিয়া সাক্ষাৎকাৰত জেলেনস্কিয়ে কয় যে ৰাছিয়াই বেলিষ্টিক ক্ষেপণাস্ত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰি আক্ৰমণ চলোৱাৰ সময়ত আগতীয়া সতৰ্কবাণী দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আমেৰিকাৰ চোৱাংচোৱা ব্যৱস্থাৰ বিশেষ গুৰুত্ব আছে। ইউৰোপীয় দেশ আৰু আন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সহযোগীসকলৰ পৰা ইউক্ৰেইনে তথ্য লাভ কৰি থাকিলেও আমেৰিকাৰ এই বিশেষ সক্ষমতাৰ বিকল্প তেওঁলোকৰ হাতত নাই বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰে।

জেলেনস্কিৰ মতে, তিনিদিন ধৰি এই বিশেষ তথ্য লাভ নকৰাৰ ফলত ৰাছিয়াৰ ক্ষেপণাস্ত্ৰ আক্ৰমণৰ আগতীয়া সতৰ্কবাণীৰ ক্ষেত্ৰত ইউক্ৰেইন সমস্যাৰ সম্মুখীন হৈছিল। অৱশ্যে, আমেৰিকাই তথ্য ভাগ-বতৰা পুনৰ আৰম্ভ কৰাত তেওঁ কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰে।



ষ্টাৰলিংকক লৈও বিতৰ্ক

ইলন মাস্কৰ কোম্পানী স্পেচএক্সৰ ষ্টাৰলিংক উপগ্ৰহ-ইণ্টাৰনেট সেৱা ইউক্ৰেইনৰ সামৰিক যোগাযোগ আৰু ড্ৰোন অভিযানৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ। জেলেনস্কিয়ে অভিযোগ কৰে যে এই সেৱাৰ ওপৰত আৰোপ কৰা কিছুমান বাধা এতিয়াও অব্যাহত আছে। তেওঁৰ মতে, এই সীমাবদ্ধতা আমেৰিকা চৰকাৰৰ পৰা অহা নিৰ্দেশৰ ফল হ'ব পাৰে।

কিন্তু আমেৰিকাৰ বিত্ত সচিব স্কট বেছেন্টে এই অভিযোগক প্ৰত্যাহ্বান জনাইছে। তেওঁৰ মতে, ৰাষ্ট্ৰপতি ড'নাল্ড ট্ৰাম্প আৰু বিদেশ সচিব মাৰ্কো ৰুবিঅ'ই প্ৰশাসনে এনে বাধা আৰোপ কৰাৰ কথা অস্বীকাৰ কৰিছে।

আমেৰিকাৰ সমৰ্থনক লৈ প্ৰশ্ন

২০২২ চনৰ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা চলি থকা ৰাছিয়া-ইউক্ৰেইন যুদ্ধত আমেৰিকাৰ সামৰিক সাহায্য, চোৱাংচোৱা তথ্য আৰু উপগ্ৰহ-যোগাযোগ ব্যৱস্থাই ইউক্ৰেইনৰ প্ৰতিৰক্ষাত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰি আহিছে। সেয়েহে, তথ্য যোগানৰ সাময়িক স্থগিতাদেশ আৰু ষ্টাৰলিংক সেৱাৰ সীমাবদ্ধতাই দুয়োখন দেশৰ সম্পৰ্কক লৈ নতুন প্ৰশ্নৰ সৃষ্টি কৰিছে।

অৱশ্যে, শেহতীয়া ঘটনাৰ ভিত্তিত আমেৰিকাই ইউক্ৰেইনৰ সমৰ্থন সম্পূৰ্ণৰূপে প্ৰত্যাহাৰ কৰিছে বুলি ক'ব নোৱাৰি। বৰং, চোৱাংচোৱা তথ্যৰ যোগান পুনৰ আৰম্ভ হোৱাৰ বিপৰীতে উপগ্ৰহ-যোগাযোগৰ সীমাবদ্ধতাক লৈ মতবিৰোধ অব্যাহত থকাটোৱে ৱাশ্বিংটন আৰু কিৰৱ মাজৰ জটিল সম্পৰ্ককে প্ৰতিফলিত কৰিছে।

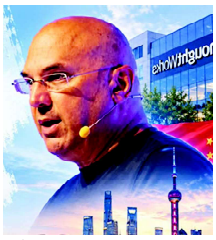
ভাৰতৰ পৰা ফ্ৰান্সলৈ প্ৰতিবাদৰ আঁৰত ছিংঘামৰ নেটৱৰ্ক?

জন জন বিচাৰ
...✍ নতুন দিল্লী

ভাৰতৰ পৰা ফ্ৰান্সলৈ বিভিন্ন দেশত চলি থকা প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীৰ মাজত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সংগঠনৰ নেটৱৰ্কৰ সম্ভাব্য সম্পৰ্কক লৈ নতুনকৈ বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈছে। আমেৰিকাৰ ফক্স নিউজ ডিজিটেলৰ ২০ অক্টোবৰত প্ৰকাশিত এক প্ৰতিবেদনত নেভিল ৰয় ছিংঘামৰ সৈতে জড়িত বুলি উল্লেখ কৰা সংগঠনসমূহকে ধৰি ৰত্নৱটা সংগঠনৰ কথা উত্থাপন কৰা হৈছে। প্ৰতিবেদনখনৰ দাবী অনুসৰি, এই সংগঠনসমূহে বিভিন্ন দেশৰ প্ৰতিবাদৰ আয়োজন, সমন্বয় অথবা প্ৰচাৰত ভূমিকা পালন কৰিছে। অৱশ্যে, এই নেটৱৰ্কে ভাৰতৰ প্ৰতিবাদসমূহৰ বাবে ধন যোগান ধৰিছে বা সেইবোৰ পৰিচালনা কৰিছে বুলি প্ৰমাণিত হোৱা নাই।

এই বিতৰ্কৰ কেন্দ্ৰত আছে নেভিল ৰয় ছিংঘাম। ১৯৫৪ চনত জন্মগ্ৰহণ কৰা ছিংঘাম এগৰাকী আমেৰিকাত জন্মগ্ৰহণ কৰা প্ৰযুক্তি উদ্যোগী আৰু ছ'ফটৰৰ পৰামৰ্শদাতা প্ৰতিষ্ঠান থটৱৰ্কছৰ প্ৰতিষ্ঠাপক তথা প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ। ২০১৭ চনত তেওঁ প্ৰতিষ্ঠানটো বিক্ৰী কৰাৰ পিছত বিভিন্ন ৰাজনৈতিক, সামাজিক আৰু সংবাদ মাধ্যম-সম্পৰ্কীয় সংগঠনলৈ আগবঢ়োৱা আৰ্থিক সহায়ৰ অভিযোগৰ সৈতে তেওঁৰ নাম চৰ্চালৈ আহে। তেওঁ বৰ্তমান চীনৰ ছাংহাইত থাকে বুলি বিভিন্ন প্ৰতিবেদনত উল্লেখ কৰা হৈছে।

ফক্স নিউজৰ সাংবাদিক আছৱা



কিউ. নোমানিৰ প্ৰতিবেদনত বিভিন্ন দেশৰ বাওঁপন্থী, সমাজবাদী, ছাত্ৰ, শ্ৰমিক আৰু সামাজিক আন্দোলনৰ সৈতে জড়িত সংগঠনসমূহৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছে। প্ৰতিবেদনখনত ভাৰতৰ নিৰ্বাচনী তালিকা সংশোধনৰ বিৰুদ্ধে চলা প্ৰতিবাদৰ লগতে ফ্ৰান্স, স্পেইন আৰু আলবেনিয়াৰ আন্দোলনৰ প্ৰসংগও উত্থাপন কৰা হৈছে। ইয়াত প্ৰগ্ৰেছিভ ইণ্টাৰনেশ্যনেল আৰু ফ্ৰান্সভিত্তিক ইণ্ডিয়ান এলায়েন্স পেৰিছৰ দৰে সংগঠনৰ ভূমিকাৰ কথাও উল্লেখ আছে।

কিন্তু বিভিন্ন দেশৰ প্ৰতিবাদৰ বিষয়ে একে ধৰণৰ বাৰ্তা প্ৰচাৰ কৰা, আন্দোলনসমূহৰ প্ৰতি সমৰ্থন প্ৰকাশ কৰা আৰু সেইবোৰৰ মাজত প্ৰত্যক্ষ সমন্বয় স্থাপন কৰা-এই তিনিওটা পৃথক বিষয়। সেয়ে একে প্ৰতিবাদী বিষয়ত সংগঠনসমূহৰ আগ্ৰহ থকাৰ পৰাই সকলো আন্দোলন একেটা কেন্দ্ৰৰ পৰা পৰিচালিত হৈছে বুলি সিদ্ধান্ত ল'ব নোৱাৰি।

এই প্ৰতিবেদনক কেন্দ্ৰ কৰি বিজেপিয়ে কংগ্ৰেছৰ সৈতে ছিংঘামৰ নেটৱৰ্কৰ সম্ভাব্য সম্পৰ্ককক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে।

GAURANSHI
INDUSTRIES

Gunika™

Purity in Every Drop, Nature in Every Product.

100% NATURAL

PURE NATURAL GOODNESS







NO ADDITIVES
BOOSTS IMMUNITY
RICH IN ANTIOXIDANTS
ECO FRIENDLY



TEA

NAME	MAKHANA (FOX NUT SUPERFOOD)	ASSAM CTC TEA	ASSAM CTC TEA
SIZE	200gm	250gm	100gm

HONEY







NAME	MORINGA HONEY	TULSI HONEY
SIZE	200gm	200gm







NAME	MUSTARD HONEY	LITCHI HONEY	WILD FOREST HONEY
SIZE	200gm	200gm	200gm

RAW & UNPROCESSED
PURE & NATURAL
DIRECTLY FROM OUR FARMS
TRUSTED BY THOUSANDS

3rd Floor, IIT Road,
Jayguru, Amingaon,
Kamrup, Assam - 781031, India

Contact :
+91-88224 20619

E-Mail :
gauranshiind@gmail.com
www.gauranshiindustries.com

VOICE OF ALL, FOR ALL

WEEKLY

JAN JAN VICHAR

Guwahati, Friday, 23 October 2026





Earthquake Hits Tibet, 16 Dead and 54 Injured

New Delhi: A powerful 7.0-magnitude earthquake struck Tibet on Thursday evening, killing at least 16 people and injuring 54 others, according to reports from Chinese state media. The tremor caused extensive damage in Nagqu city in northern Tibet, where hundreds of houses and livestock enclosures reportedly collapsed.

Authorities have launched rescue and relief operations in the affected areas, deploying more than 1,600 rescue personnel. Emergency supplies have also been dispatched, including around 3,000 tents, 1,000 prefabricated housing units, folding beds, torches and winter clothing to support people displaced by the disaster.

According to the US Geological Survey (USGS), the earthquake occurred at a depth of approximately 18 kilometres, with its epicentre around 191 kilometres east-northeast of Nagqu. The affected area lies in a sparsely populated, high-altitude region of northern Tibet. Nagqu is situated more than 300 kilometres north of Lhasa, the Tibetan capital.

Data released by India's National Centre for Seismology (NCS) recorded 18 seismic events across Tibet, China and Myanmar between the night of October 22 and 12:51 am on October 23. These included 13 events in Tibet, four in China and one in Myanmar.

The strongest earthquake, measuring 7.0 on the Richter scale, was recorded in Tibet at 8:03:42 pm Indian Standard Time on October 22. Several subsequent tremors were also reported, with magnitudes ranging from 4.3 to 5.0.

Bihar's Electoral Roll Gains 14 Lakh Voters After SIR

Jan Jan Vichar
...✍PATNA



Bihar's electoral roll has added nearly 14 lakh voters since the publication of the post-Special Intensive Revision (SIR) list in September 2025, taking the state's electorate to approximately 7.55 crore, according to officials associated with the Chief Electoral Officer's (CEO) office.

The latest electoral roll, updated on October 1, 2026, contains around 7.55 crore voters, compared with 7.41 crore in the list published after the SIR exercise concluded on September 30, 2025. Officials said approximately 18.7 lakh applications were submitted using Form 6, the prescribed form for inclusion of a name in the electoral roll under the Registration of Electors Rules, 1960. Of these, nearly 14 lakh applications resulted in successful enrolment.

The increase includes first-time voters, young people reaching voting age and individuals seeking to have their names restored to the electoral roll.

Enrolment Usually Rises Before Elections

Electoral officials said voter enrolment generally increases during election years, whether ahead of Lok Sabha, Assembly or Panchayat elections. Bihar recorded an increase of around 41.9 lakh voters in 2023–24, the year of the Lok Sabha elections, and approximately 41.4 lakh in 2024–25, when Assembly elections were held in the state. In comparison, the increase was around 13 lakh in 2022–23 and 24.5 lakh in 2025–26, according to figures cited by officials. The latest addition of nearly 14 lakh voters comes after the intensive revision exercise, which significantly changed the composition and size of the state's electoral roll.

SIR Removed and Restored Names After Verification

The three-month SIR exercise was conducted in Bihar between June 25 and September 30, 2025. It was the first exercise of its kind in the current nationwide series.

Before the revision, the state had approximately 7.89 crore registered voters. During the initial exercise, around 65.6 lakh names were removed from the rolls. These included approximately 22.3 lakh voters reported dead, 36.4 lakh who had shifted residence and 6.8 lakh entries identified as duplicated across locations.

During the subsequent claims and objections period, approximately 21.5 lakh voters were added, while another 3.6 lakh names were removed. The final post-SIR electoral roll contained around 7.41 crore voters. Bihar has not conducted a summary revision of the electoral roll since the 2025 SIR exercise, officials said.

Form 6 Applications Under Scrutiny

All individuals added to the electoral roll after the SIR, including first-time voters, were required to submit Form 6. Booth-level officers (BLOs) have been examining applications and verifying supporting documents before recommending names for inclusion. Electoral Registration Officers (EROs) conduct further scrutiny before approving enrolment. In Patna's Raja Bazar area, a booth-level officer said most applicants had submitted their forms online through the Election Commission of India portal. She added that enrolment activity generally gathers pace before elections, while officials working as teachers are currently occupied with academic responsibilities.

In Thakurganj Nagar Panchayat in Kishanganj district, a BLO received around 3,600 applications over the past year and recommended approximately 636 names for inclusion after verification. Seven additional applications were being examined after a mobile application flagged them as possible duplicate entries. The Election Commission's Demographic Similar Entry (DSE) software identifies potentially similar records by comparing details such as names, fathers' names and ages. Such flags require verification and do not, by themselves, establish that an entry is duplicate. In Patna's Kadamkuan area, a BLO assigned to booth number 419 at a school for visually impaired students received around 24 applications over the past year.

Separate Declaration Not Required for Form 6

The latest enrolment drive follows a communication from the Election Commission stating that eligible citizens applying through Form 6 need not submit a separate declaration seeking parental linkage with the previous SIR. The Bihar CEO's office has also been asked to organise a campaign to identify and enrol first-time voters and eligible citizens left out of the electoral roll.

Petrol Bomb Attack on Building Housing ED Office in Shillong

Jan Jan Vichar
...✍Shillong

Security concerns have mounted in Meghalaya's capital after two motorcycle-borne men allegedly hurled petrol bombs at a building housing the Enforcement Directorate (ED) office in Shillong early Thursday, marking the second attack on a government establishment in the city within two days. The incident took place in the Langkyrding area of East Khasi Hills district. No structural damage to the building was reported, Superintendent of Police Vivek Syiem said. According to the police, the guard stationed inside the building was unaware of the incident until Thursday morning. Investigators are examining CCTV footage in an effort to identify the suspects, while a case is being registered in connection with the attack. Police have also intensified patrolling in the area as the investigation continues. The latest incident follows a similar attack on the Health Department office in Shillong's Laitumkhrah area on Wednesday morning. The back-to-back incidents have raised questions about the security of government establishments in the Meghalaya capital. Although no structural damage was reported in the latest attack, the use of petrol bombs against a building housing a central investigative agency has added to concerns over public security.

Menga Mandir: Arunachal's Ancient Cave Shrine Where Lord Shiva Is Worshipped as Lakulisha

Jan Jan Vichar
...✍Itanagar



In the hills of Arunachal Pradesh, where rugged landscapes shelter places of worship shaped by nature and tradition, Menga Mandir stands apart. Also known as the Meghna Cave Temple, this natural rock shrine near Daporijo, in Upper Subansiri district, draws devotees with its unusual cave formations and its distinctive form of Shiva worship. Unlike temples built around elaborate architecture, Menga Mandir is formed within a natural cave. Its spiritual centre is a large stalagmite-a mineral formation created over time by the deposition of minerals from dripping water-which devotees revere as a Svayambhu Shiva Lingam, or a self-manifested representation of Lord Shiva. But the temple's significance goes beyond its natural beauty. Here, Shiva is worshipped as Lakulisha, a revered figure in the Shaivite tradition associated with one of the important historical schools of Shaivism. Lakulisha is traditionally regarded as the 28th incarnation of Shiva, giving the shrine a distinctive place in the region's religious landscape.

A journey into the heart of the cave

Reaching Menga Mandir involves climbing a flight of steps along a hillside. The approach offers a transition from the open landscape outside to the cave's dark and enclosed interior. Inside, the natural rock formations create an atmosphere markedly different from that of a conventional temple. The cave contains two dark passages, one of which begins with a relatively broad entrance before narrowing sharply. Further inside, the passage becomes so constricted that visitors may have to crawl to move ahead. These confined tunnels are among the cave's most striking features. They make the visit not merely an act of worship but also an encounter with a natural space whose shape and scale have been determined over centuries by geological processes. The cave's darkness, uneven rock surfaces and narrow passages add to its sense of mystery. For devotees, however, the central attraction remains the sacred rock formation worshipped as Shiva.

Where faith meets history

Regional accounts associate the cave with a history extending back approximately 5,000 years, while its rediscovery is said to have taken place in 1962. Such claims contribute to the shrine's reputation as an ancient place of worship, although independently verified archaeological evidence would be needed to establish its precise age.

Inscriptions within the cave have also been described as references to ancient Sanskrit religious texts associated with the Kali Purana. These reported connections add another layer to the temple's significance, linking its local traditions with the wider history of Hindu religious literature. The distinction between religious belief and documented history is important here. The cave's naturally formed shrine is visible, while claims about its antiquity and textual associations require careful historical verification. Together, however, these traditions help explain why Menga Mandir occupies a special place in the spiritual imagination of the region.

A distinctive Shaivite tradition in the Northeast

Arunachal Pradesh is known for its diverse cultural and religious traditions, shaped by its geography, communities and historical connections with neighbouring regions. Menga Mandir adds to this landscape through its association with Lakulisha and the worship of a naturally formed Shiva Lingam. The shrine also illustrates how places of worship can emerge from the relationship between landscape and belief. Rather than imposing a structure upon nature, the temple's sacred identity is closely tied to the cave itself.

For pilgrims, the visit offers an opportunity to pray and experience a place where the natural rock formation is central to worship. For travellers interested in the cultural heritage of the Northeast, the cave presents a different perspective on the region's religious geography—one that is rooted in a specific landscape and a distinctive tradition.

More than a destination

Menga Mandir is not simply a cave with an unusual rock formation. It is a place where natural geology, religious devotion and regional tradition converge. Its narrow passages and dark chambers may attract the curious, but its enduring importance lies in the faith attached to the sacred formation within. The worship of Shiva as Lakulisha gives the shrine a distinctive identity, while the cave's physical features make the experience unlike that of many conventional temples. As interest in Arunachal Pradesh's cultural and natural attractions grows, Menga Mandir offers a reminder that the Northeast's heritage is not confined to monuments, monasteries or celebrated tourist sites. Some of its most compelling stories are found in quieter places, where the landscape itself becomes part of the sacred experience.

At Menga Mandir, the cave is both the setting and an essential part of the story-a natural sanctuary where faith finds expression in stone.

NETANYAHU INVITES MODI & MACHCHHAR

Jan Jan Vichar
...✍NEW DELHI/JERUSALEM

In a gesture highlighting India–Israel ties and recognition of an Indian pilot's actions during a mid-air emergency, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu has invited Prime Minister Narendra Modi and Captain Smit Machchhar to jointly light a ceremonial torch at Israel's Independence Day celebrations in 2027.

The invitation was extended during a telephone conversation between Netanyahu and Modi on Thursday, October 22. The Israeli leader praised Machchhar, a Flydubai captain who was seriously injured when his co-pilot allegedly attacked him inside the cockpit of a Dubai-to-Tel Aviv flight on September 30.

Netanyahu announced the invitation in a post on X, saying Modi had thanked him and emphasised the longstanding relationship between the two countries. According to Netanyahu, Modi also said that India and Israel were fighting terrorism together, both on land and in the air.

Captain Machchhar, a Gujarat-born Indian commercial pilot, was operating Flydubai flight FZ1073



when the reported attack occurred. According to accounts of the incident, the co-pilot allegedly struck him repeatedly inside the cockpit while the aircraft was flying over Saudi airspace.

Despite sustaining serious head and arm injuries, Machchhar managed to open the cockpit door, allowing other crew members and a fellow captain to intervene and restrain the attacker. The aircraft subsequently made an emergency landing in Saudi Arabia.

The incident triggered an investigation into the circumstances surrounding the attack and the aircraft's rapid loss of altitude. Reports said the plane descended by approximately 17,000 feet during the emergency. All passengers and crew survived.

Netanyahu had previously spoken to Machchhar and described him as a hero of India, Israel and the wider world. The proposed torch-lighting ceremony would give the Indian pilot a prominent role in Israel's national Independence Day celebrations.

However, the ceremony's participants are selected through an established Israeli government process, meaning the invitation does not by itself guarantee final selection.

The latest conversation between the two leaders also focused on the progress of India–Israel relations and the volatile situation in West Asia. In a statement posted on X, Modi said the leaders reviewed the sustained momentum in bilateral relations and reaffirmed their commitment to strengthening the partnership. They also exchanged views on developments in West Asia and stressed the urgent need to restore peace and stability in the region.

India and Israel have expanded cooperation across defence, security, technology, agriculture and innovation. The two countries have also sought to strengthen their strategic partnership while maintaining diplomatic engagement on regional and international issues. The proposed joint appearance at Israel's Independence Day ceremony carries diplomatic significance, bringing together the Indian prime minister and a civilian pilot whose actions during a reported cockpit attack drew international attention.

For India, the episode has placed the spotlight on the role of professional training, presence of mind and crew intervention in an aviation emergency. For Israel, the invitation provides an opportunity to publicly acknowledge the pilot's actions while underscoring the longstanding relationship between the two countries.

Retired Customs Officer's Murder: Main Accused Arrested at Kolkata Airport

Jan Jan Vichar
...✍Patna/Ara

The Bihar Special Task Force (STF), in coordination with Bhojpur Police, has arrested Chandan Singh, the main accused in the murder of retired Assistant Customs Commissioner Ram Kumar Singh. He was apprehended on Monday at Netaji Subhas Chandra Bose International Airport in Dum Dum, Kolkata, while allegedly attempting to flee to Nepal.

According to police sources, Chandan Singh had been absconding since the murder took place on October 15. Investigators suspect that he was trying to evade arrest by leaving the country through Nepal. Bhojpur Superintendent of Police Awadhesh Dixit confirmed the arrest, saying the accused was being brought to Ara on transit remand. He added that another suspect, Manoj Singh alias Vicky, had already been arrested and that Chandan would be questioned after reaching Ara

Land Dispute Suspected as Motive

Police suspect that a land dispute may have led to the murder. According to the deceased's family, Chandan Singh and his associates had allegedly threatened Ram Kumar Singh over a plot situated in a prime location.

The deceased's son, Amit Kumar alias Goldy, named the land dispute in the FIR lodged in connection with the killing. Investigators are examining the allegations to establish the motive and determine the roles of those involved. Chandan Singh has previously faced allegations relating to land grabbing, according to the supplied report. However, the allegations and their connection to the present case remain subject to investigation.

Retired Officer Shot While Leaving for Morning Walk

Ram Kumar Singh was attacked by three motorcycle-borne assailants while leaving his residence for his morning walk on October 15. He was taken to Ara Sadar Hospital, where doctors declared him brought dead.

The killing triggered protests by local residents, who demanded the immediate arrest of the perpetrators. Protesters also blocked the Ara–Patna Road. The blockade was lifted after police officials assured them that action would be taken. The arrest of the alleged main accused is expected to advance the investigation, though police questioning and further evidence collection will be crucial to establishing the sequence of events.

Family Raises Allegations Against Local Officials

The deceased's family also accused Mufassil police station SHO Ram Kalyan Yadav and revenue employee Vishnu Deo Singh of allegedly being in collusion with Chandan Singh. These are allegations made by the family and have not been established as fact. Their validity, if part of the formal investigation, will need to be examined by the authorities.

Meanwhile, Chandan Singh's wife, Chandani Singh, has claimed that her husband is innocent and has been falsely implicated. In a recorded video statement, she acknowledged that her husband had differences with the deceased over a plot of land but denied the allegations against him. She also said she had been living with her parents for the past three months.

Police Investigation Continues

With Chandan Singh in custody, police are expected to question him about the alleged land dispute, the circumstances of the attack and the identities of the other people involved. Investigators will also examine the allegations made by the deceased's family and the defence presented by the accused's wife.

EDITORIAL

Women's Quota Delimitation

The government's reported plan to convene a special session of Parliament to push through constitutional amendments on women's reservation and delimitation raises a larger question: does a parliamentary majority automatically translate into democratic legitimacy? The answer is no. Constitutional change demands more than arithmetic; it demands argument, transparency and political trust. At a time when Parliament is already caught in bitter confrontations over the NEET controversy and the Special Intensive Revision (SIR) of electoral rolls, another high-stakes legislative battle could deepen the divide. The government may believe it has the numbers, but treating constitutional amendments as a test of strength would be a grave misreading of parliamentary responsibility. Women's reservation is a long-overdue step towards more representative politics. But delimitation is far more complex. It touches the distribution of political power, the representation of states and the delicate balance of Indian federalism. Any attempt to push these changes through without adequate consultation risks turning a reform agenda into a political confrontation. Article 368 lays down the special majority required for constitutional amendments. Yet meeting the legal threshold is not the same as securing wider democratic acceptance. The government must explain its proposals, address legitimate concerns and allow Parliament to scrutinise their consequences. The Opposition, too, must look beyond disruption. Dissent is essential to democracy, but obstruction without constructive engagement serves neither Parliament nor the public. The real danger is not disagreement in Parliament; it is the belief that numbers can replace dialogue. Constitutional reform should strengthen democratic institutions, not become another instrument of partisan advantage.

Is Protest Only Means Left To Us To Take Back Democracy?

Jan Jan Vichar
...✍Aakar Patel

The three democratic tools available to us are the vote, the courts and protest. The only one over which Indians have real agency is protest. Voting is considered to be the same thing as democracy, as if democracy vanishes between elections. For decades, the election process in India has been accretive in adding prestige and credibility. That phase is behind us. The Constitution says that every Indian aged 18 or above, who is not "disqualified under this Constitution or any law made by the appropriate legislature on the ground of non-residence, unsoundness of mind, crime or corrupt or illegal practice", shall be entitled to be registered as a voter at any such election.

This direction is more like a suggestion to the present Election Commission. It assumed, no doubt on the orders of the government, that its exercise to gratuitously put crores of people through trauma would carry on undisturbed. A survey of how many rollbacks and clarifications it has issued over the last four weeks throws up a list of about one dozen. These include a "special enrolment drive" to bring in people left out by the previous special disenfranchisement drive. Then there is the removal of a declaration for some people, a waiver for in-person appearance for other people, a review of flawed software, limiting (but not ending) the malicious practice of objections being filed by third party individuals against voters, mostly Muslims of course.

Then there is the introduction of searchable voter lists after resisting them all this time for no reason other than opacity. And now private school teachers being made to do the extracurricular work that hapless public school officials have been running door to door doing, and other things besides. The number of measures shows the sloppiness with which this adventure was embarked upon. The speed at which the measures are coming betrays the panic. The disclosure that the commission's majority was being disregarded in decisions taken would have surprised few.

Voting is considered to be the same thing as democracy, as if democracy vanishes between elections. For decades, the election process in India has been accretive in adding prestige and credibility. That phase is behind us Protest is our most effective tool at getting the state to stop misbehaviour. This is why there is such energy expended by the government in attempting to curb it, limit it and throttle it. The farm laws, once Indians were mobilised in the tens of thousands and arrived in Delhi, were dead. It took a full year for the government to finally strike them down, and those months were wasted because the monarch did not want to be seen as surrendering to the people.

Will these subsequent corrections, rollbacks and reviews resolve the mess? Of course not. We have already been divided into several tiers of Indian citizens: some voters, some struck off, some in appeal, some without information about their status, some beyond care, others awaiting judgment.

This steaming pile of excrement cannot be solved by anything other than a full rollback. Alas, now with elections already having taken place, even this action will lead to problems of electoral legitimacy, for instance in Bengal. So, no. This mess is of a scale that could only have been erected by the architect of minimum government, maximum governance. The second democratic tool we have is the courts. Article 32 says our right to move court for the enforcement of fundamental rights "is guaranteed". Note that what is guaranteed is the liberty to move court. What follows from there in proceedings is something we can witness daily in this country and need not be expounded on further. Our finest lawyers have already spoken about where things stand. As with the Election Commission, there has been erosion here also.

The third democratic tool, the only one over which we have real agency, is protest. Showing up to tell the state that we feel violated and it must stop. The government can mess around with our vote, as it is doing, and the justice system can toy with us as it does in service of the executive. It is harder for it to force itself on our bodies, though it tries. Protest is our most effective tool at getting the state to stop misbehaviour. This is why there is such energy expended by the government in attempting to curb it, limit it and throttle it. The farm laws, once Indians were mobilised in the tens of thousands and arrived in Delhi, were dead. It took a full year for the government to finally strike them down, and those months were wasted because the monarch did not want to be seen as surrendering to the people. But it was immediately clear to many the moment the mobilisation happened, that the people would win. Deliciously, this victory was accompanied by an apology. An apology that was a qualified one, as may be expected from the person offering it, but an apology nonetheless. The brave Muslim women who led the protests against the National Register of Citizens succeeded in halting what has happened in Assam from happening elsewhere in India. Yes, it is true that the road this SIR has put us on ultimately takes us to the same destination, but recent events show that this will not be easy for the government to do uncontested no matter how much the BJP leadership salivates at the thought of crores of disenfranchised, disentitled and interned. Peaceful assembly (Article 19) is a fundamental right, meaning one that enjoys a high degree of protection from encroachment by the government. But in practice, the encroachment has exceeded the freedom over the decades. And there it will remain, caged in designated areas and subject to government approval. Unless it is taken back, as today it is being by young women and men on the streets of Delhi. For many of us, this is the most heartening feature of our times. A hard, authoritarian state finally challenged by a spirited public response from our youth.

Two Bangladeshis Executed in Mecca

The Unanswered Questions Behind Saudi Arabia's Shocking Verdict

Jan Jan Vichar
...✍New Delhi

Saudi Arabia's execution of two Bangladeshi nationals over what its authorities described as an "indecent act" inside a mosque in Mecca has brought renewed attention to the kingdom's strict legal system-and to the rights of foreign nationals facing its harshest punishment.

The executions were carried out on October 14, 2026, in the Mecca region. Saudi Arabia's Ministry of Interior identified the individuals as Nazrul Islam Abdul Basir and Siti Akhtar. According to the ministry, an investigation was followed by criminal charges, a court verdict imposing the death penalty and approval by the relevant judicial authority before a royal order authorised the executions.

Yet one central question remains unanswered: What exactly did the two individuals do? The Saudi statement did not identify the mosque, describe the alleged act in detail or disclose the evidence presented in court. Social media speculation has suggested that the case involved physical intimacy, but such claims should not be treated as established fact. The available official statement does not confirm them.

Bangladesh learned of the executions after they happened

The controversy has taken on a diplomatic dimension because Bangladesh says its government and diplomatic mission in Saudi Arabia were not informed before the executions. Following the announcement, Bangladesh's Consulate General in Jeddah sought formal clarification from Saudi authorities. Dhaka subsequently raised the matter with the Saudi ambassador and requested details about the allegations, the judicial proceedings and the reasons its diplomatic mission had not been informed in advance. As of October 21, Bangladesh was still awaiting a substantive response, according to a Reuters report. The government said it would consider its next steps after receiving the relevant information and court documents.

The absence of advance notification has become a particularly sensitive issue. Consular access can be crucial for foreign nationals who may face language barriers, unfamiliar legal procedures and difficulties securing legal representation in another country.

However, the precise legal implications of the notification issue cannot be settled without the full case record. Article 36 of the Vienna Convention on Consular Relations provides for communication with and access to a foreign national's consular authorities, including notification without delay when the detained person requests it. Whether and how those requirements applied in this particular case needs to be assessed against the facts, including what the authorities knew and what steps were taken during the proceedings.

What does ta'zir mean—and why does it matter? Saudi Arabia said the death sentences were imposed under ta'zir, a category of punishment in Islamic jurisprudence that gives judges discretion within the applicable legal framework for offences whose penalties are not fixed in the same way as prescribed punishments.

The Saudi ministry cited the gravity of the offence and the violation of the mosque's sanctity as reasons for the sentences. It said the verdicts had been upheld by the relevant judicial authority before the executions were authorised.

The term itself, however, does not explain why the death penalty was considered appropriate in this case. Nor does it establish that every act described as immoral or improper at a religious site automatically carries a death sentence. That distinction matters. The severity of a punishment makes the clarity of the charges, the quality of evidence, the opportunity to mount a defence and the availability of judicial review especially important. Without the judgments and a fuller account of the proceedings, outsiders cannot independently assess the court's reasoning.

The question is not whether a country can regulate conduct at its religious sites. It is whether the details of a case involving the ultimate punishment are sufficiently clear for the public to understand the legal basis on which that punishment was imposed.

A sacred place, a severe punishment

Mecca occupies a unique place in Islam, and its sacred sites hold profound religious significance for Muslims across the world. Saudi Arabia has consistently maintained that it must protect the sanctity and security of these locations. For the Saudi authorities, the case was presented as enforcement of the law against conduct they considered a serious violation of a mosque's sanctity. But the lack of publicly disclosed details has left a gap between the official justification and the information available to the wider public. The distinction between religious reverence and judicial scrutiny should not be overlooked. Respect for a sacred place and questions about the fairness and transparency of legal proceedings are not necessarily opposing positions. A legal system's credibility rests not only on its ability to punish offences but also on its ability to explain the basis of its decisions, particularly when the consequences are irreversible. It is also important not to treat Saudi Arabia's legal interpretation as representative of every Muslim-majority country or of all Muslims. Legal systems and interpretations of Islamic jurisprudence vary across countries and institutions.

The stakes for Bangladesh's migrant workers

The case carries wider significance because Saudi Arabia is a major destination for Bangladeshi migrant workers. Reuters reported that an estimated 3.5 million Bangladeshis live and work in the kingdom, sending remittances that support households and contribute to Bangladesh's economy.

For a migrant worker, arrest in a foreign country can mean separation from family, uncertainty over legal representation and limited access to information about proceedings. The risk is especially serious when a case could result in a death sentence.

The executions have therefore placed the question of consular protection under scrutiny. Bangladesh needs to establish when the two individuals were detained, what charges they faced, whether they had access to legal assistance, what opportunities they had to challenge the verdicts and why the diplomatic mission was not notified before the sentences were carried out.

Some of these questions may be answered only when Saudi Arabia provides the requested records. Until then, conclusions about the precise conduct, the evidence or any procedural failure would be premature.

The case also presents a challenge for Bangladesh's diplomatic system: how can its missions identify vulnerable nationals, monitor serious criminal cases and intervene effectively when thousands of citizens are held in detention across a foreign country?

The verdict is final, but the questions remain

Saudi Arabia says the two Bangladeshis were convicted, their sentences were upheld and the executions were authorised through the kingdom's legal process. Bangladesh, meanwhile, is seeking the detailed information needed to understand what happened and why it was not informed beforehand. The central facts are stark: two people have been executed; the precise act described by Saudi authorities has not been publicly specified in the ministry's statement; and Bangladesh says it learned of the executions after they had taken place. This case should not be reduced to unverified social media claims, nor should the seriousness of the punishment be used to close off legitimate questions. The full court judgments, evidence and explanation of the consular communication process are essential to a clearer understanding. A sacred site's dignity is a matter of profound importance to believers. So, too, is the need for justice to be demonstrably fair, especially when the punishment cannot be reversed. Until the outstanding details are disclosed, the execution of the two Bangladeshis remains not only a case of severe punishment, but also a test of transparency, consular protection and public confidence in the administration of justice.

A Rs 35-Lakh Singer, an Angry Minister and a Humiliated Audience

Jan Jan Vichar
...✍Entertainment Desk

In India, a stage is rarely just a stage. It is a platform for celebrity, a display of political influence, a source of public entertainment and, sometimes, a reminder of how power operates. At Uttarakhand's Kunjapuri Mela, all these elements collided when Cabinet Minister Subodh Uniyal walked onto the stage during Daler Mehndi's performance and questioned the singer's ability to deliver the show.

The minister alleged that the veteran Punjabi singer appeared intoxicated, questioned whether he was singing live and said he had been paid Rs 35 lakh for the performance. Videos of the confrontation quickly spread across social media, turning a cultural event into a national controversy. The allegation of intoxication, however, has not been independently established.

The incident raises a distinctly Indian question: when an artist is paid a substantial fee to perform at a public event, who is accountable to whom-the performer to the audience, the organiser to the public, or the politician to everyone watching?

The audience is not an extra

India has an enduring fascination with celebrity. A famous singer can attract thousands of people, command a substantial fee and turn an ordinary cultural programme into a major attraction. But the public often disappears from the conversation once a controversy begins.

The Kunjapuri incident is a case in point. The minister argued that people had gathered to hear



Mehndi and deserved a performance worthy of the occasion. His stated grievance was that the singer was not doing justice to his reputation or the money spent on bringing him to the event.

That concern cannot simply be dismissed. Whether the money came from public funds, sponsorship or an event budget, a substantial professional fee creates legitimate expectations. The organisers must ensure that the contracted performance is delivered, and the artist must communicate honestly if illness or another difficulty makes that impossible.

But there is an equally important distinction: demanding accountability is not the same as publicly humiliating someone. A minister's displeasure does not automatically justify turning a performance into a confrontation before a crowd.

When political power enters the spotlight

The most striking feature of the episode is not merely the accusation against a singer. It is the manner in which a political office-holder intervened.

A minister has the authority to raise concerns about an event, question its arrangements and seek explanations from organisers. But a public stage is not a disciplinary chamber. The higher the office, the greater the responsibility to exercise restraint.

In India, public events frequently bring together politicians, celebrities and officials. Their presence can lend prestige to a programme, but it can also create an imbalance of power. When a disagreement occurs, the politician's words carry a weight that an ordinary organiser's complaint may not.

That is why the method of intervention matters. If a performer fails to meet contractual obligations, the appropriate response is to document the shortcoming, seek an explanation and invoke the agreed terms. A public confrontation may generate headlines, but it does not necessarily establish the truth.

A familiar Indian habit Worship the star, then condemn him

The reaction from the entertainment industry revealed another contradiction. Several celebrities defended Mehndi, with his brother Mika Singh and actor Anupam Kher referring to health concerns and arguing that the singer deserved dignity. Singer Sona Mohapatra, meanwhile, raised questions about professional accountability and the audience's expectations.

Both concerns deserve examination. India often treats established entertainers as institutions in their own right. Their achievements become part of popular culture, and their fans develop a deep emotional attachment to them. But a long career cannot guarantee that every performance will be satisfactory. Equally, a disappointing performance cannot erase decades of contribution to music. The relevant question is not whether Daler Mehndi is a legend. His place in Indian popular music can be acknowledged without assuming that every criticism of his work is an insult. Nor should one difficult appearance become grounds for an unverified accusation about his personal conduct. The allegation that Mehndi was intoxicated remains unproven in the available reporting.



Printed & Published by Purvanchal Prints, GMCH Road, Harbala Market, Bhangagarh, Guwahati-781005 Contact: 69001 26012
Email : Official.janjanvichar@gmail.com,Website : www.janjanvichar.in ● Executive Editor : Subhash Kumar Choudhary ● Editor : Dhaneshwar Choudhary